PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 213 ● भिलाई, शनिवार 28 फरवरी 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

पहला कॉलम

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने किया तीन सदस्यीय पैनल का पुनर्गठन

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति का पुनर्गठन कर दिया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से 25 फरवरी को जारी अधिसूचना के मुताबिक, पुनर्गठित समिति 6 मार्च से प्रभावी होगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा बुधवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अरविंद कुमार पुनर्गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य सदस्य होंगे। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पुनर्गठित पैनल 6 मार्च से प्रभावी होगा।

डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में किया बदलाव

नई दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में संशोधन किया है। अब यात्री हवाई टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या बदल सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। डीजीसीए ने यात्रियों के अनुकूल संशोधित नियम जारी किए हैं। इसके तहत एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि यात्री टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में कोई गलती दिखाए और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो, तो इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। डीजीसीए ने कहा, यदि टिकट ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि हैं। एयरलाइन यह सुनिश्चित करें कि रिफंड प्रक्रिया 14 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो।

9 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत, स्कूल में खेलते समय गिरी, भाई की भी ऐसे ही गई थी जान

नई दिल्ली। राजस्थान के नागौर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गोटन कस्बे के एक निजी स्कूल में 9 साल की छात्रा की कथित हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना 23 फरवरी की सुबह करीब 7:48 बजे की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। यह हादसा गोटन स्थित गोटन इंटरनेशनल स्कूल में हुआ। स्कूल प्रशासन के अनुसार, तालनपुर निवासी राजेंद्र बापेडिया की बेटी दिव्या कक्षा पांचवीं की छात्रा थी। वह रोज की तरह स्कूल पहुंची थी। प्रार्थना सभा शुरू होने से पहले कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे। जिनमें दिव्या भी शामिल थी। स्कूल डायरेक्टर रामकुंवार ओला के मुताबिक, खेलते-खेलते दिव्या अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इससे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया

बालोद विधायक ने कहा क्षेत्र में करोड़ों के काम अटके..विपक्ष का वाक आउट

रायपुर। संवाददाता

विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया कि बजट में स्वीकृत हो चुके मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग से जुड़े करोड़ों के काम लंबे समय से अटके हुए हैं। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इससे इंकार किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की कि यदि काम अटके भी हुए हैं तो इसी सदन में स्वीकृति की घोषणा कर दें। वित्त मंत्री ने नियम प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा कर पाना संभव नहीं। इसके विरोध में सारे कांग्रेस विधायकगण नारेबाजी करते हुए सदन से वाक आउट कर गए। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा का सवाल था कि संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के बजट में सम्मिलित किन कार्यों के लिए 3 फरवरी 2026 की स्थिति में कितनी राशि की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है? कितनी राशि के कौन से कार्य वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के पास किन कारणों से तथा कब से लंबित हैं एवं इन कार्यों को कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ?वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी की ओर से जवाब आया कि विभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत नवीन कार्यों के लिए 1 मई 2012 की स्थिति में 3 करोड़ तक के प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार प्राप्त थे, जिसे 14 मई 2025 में बढ़ाकर रू. 5 करोड़ किया गया, ताकि कार्यों की स्वीकृति में गति आए। प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश संबंधित विभाग व्दारा जारी किए जाते हैं। 3 फरवरी 2026 की स्थिति में वित्त विभाग में संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के कोई भी प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति पर सहमति हेतु लंबित नहीं है। श्रीमती सिन्हा ने कहा कि मेरे क्षेत्र में चाहे पीडब्लूडी हो या एरिकेशन, सभी तरफके काम लंबित हैं। सभी कार्य वित्त में जाकर अटके हुए हैं। चौधरी ने कहा कि बजट में प्रावधानित कोई भी कार्य वित्त विभाग में सहमति के लिए आता है। आपके क्षेत्र में कई कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। बहुत सारे वित्तीय मसलों का रिफॉर्म हुआ है। बजट में नवीन मद की परिभाषा में संशोधन किया गया। पहला संशोधन 2011 में हुआ था, 2024 में फिर किया गया। प्रशासकीय स्वीकृति 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। ज्यादा से ज्यादा प्रशासकीय स्वीकृति हो सके इसलिए वित्तीय रीफॉर्म किया गया। बजट में बरसों से जो प्रावधान चले आ रहा था उसकी जगह वित्तीय प्रावधान बढ़ाया गया।पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आपने पूरी प्रक्रिया बता दी। बालोद का बताएं। बालोद तो जीरो है।

फ्लाई ऐश एवं कोल डस्ट अवैध डंपिंग पर विधानसभा में चला आरोप-प्रत्यारोप

रायपुर। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने फ्लाई ऐश एवं कोल डस्ट की अवैध डंपिंग के मामले को उठाया। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी व्दारा यह कहे जाने पर कि ऐसे मामलों में पिछली सरकार की तुलना में हमारी सरकार ज्यादा कार्यवाही कर रही है, कांग्रेसी विधायगण भड़क गए और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए वाक आउट कर गए। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक उमेश पटेल का सवाल था कि रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित उद्योगों में कितने कितने उद्योगों से फ्लाई ऐश डंप किया जाता है? वर्ष 2023-24, 2024-25 से लेकर विगत 4 फरवरी तक की स्थिति में अवैध पलाई ऐश डम्प किए जाने के कितने मामले सामने आए और क्या कार्यवाही की गई? क्या बिना अनुमति के फ्लाइ ऐश डम्प करने का मामला प्राप्त हुआ है? रायगढ़ जिला के फ्लाई ऐश एवं कोयला परिवहन के कारण दूषित पर्यावरण के सुधार हेतु क्या कार्य योजना है? आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी की तरफसे जवाब आया कि उक्त अवधि में रायगढ़ जिला अंतर्गत 24 ताप विद्युत संयंत्रों व्दारा राख का उपयोग भू-भराव/खदान भराव में किया जा रहा है। उक्त ताप विद्युत संयंत्रों में से 6 ताप विद्युत संयंत्रों व्दारा स्वयं के निर्मित ऐश डाईक में भी अस्थाई रूप से राख का भण्डारण किया जाता है।

वायनाड में खुद बताई पूरी कहानी

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच क्यों हो गई अनबन?

नई दिल्ली/ एजेंसी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी से अनबन की कहानी साझा की है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फिर से कैसे दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू हुई और इस सुलह में प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड का क्या कुछ योगदान था। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो साझा किया है। जिसमें वह अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में एक दिलचस्प किस्से को साझा कर रहे हैं। राहुल ने बताया कि वायनाड ने भाई-बहन के बीच के गतिरोध को किसी भी शांति वार्ता से कहीं ज्यादा तेजी से सुलझा दिया था। साझा किए गए वीडियो में राहुल गांधी 2024 के वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के लिए पार्टी द्वारा बनाए जा रहे घरों के शिलान्यास समारोह में बोल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राजनीति में अपने 22 वर्षों पर विचार करते हुए तर्क दिया कि राजनेताओं को अपने बारे में अधिक खुला और पारदर्शी होना चाहिए। राहुल ने कहा कि मैं 2004 से राजनीति में हूं, तकरीबन 22 साल बीत चुके हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, चीजों के बारे में सोचने का आपका तरीका बदलने लगता है। उन्होंने कहा कि एक बात जिस पर मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं वह यह कि राजनेताओं को अपने बारे में अधिक खुलकर बोलना चाहिए। रायबरेली सांसद ने वायनाड के लोगों को अपना परिवार बताते हुए हाल ही में हुए घरेलू तनाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मेरी बहन कल मुझसे बात नहीं कर रही थी, उसकी चुप्पी इतनी गहरी थी कि मुझे अपनी मां सोनिया गांधी से इसका जिक्र करना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि जब मेरी मां ने मेरी बहन के बारे में पूछा तो मैंने उनसे कहा कि वह परेशान हैं

हेट स्पीच के मामले में

असम के फायरब्रांड सीएम हिमंत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

नई दिल्ली। आए दिन अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले असम सीएम हिमंत सरमा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, दरअसल, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी किया है। दायर याचिका में असम के सीएम सरमा को राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफहेट स्पीच देने से रोकने की मांग उठाई गई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जनहित याचिका में कहा गया है कि सीएम सरमा के कथित हेट स्पीच के सार्वजनिक वीडियो होने के बावजूद भी असम पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज नहीं की है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई ना होने की वजह से राज्य में भय का माहौल पौदा होता है। यह याचिका डॉ. हिरेन गोहेन और दो अन्य ने दायर की थी, जिसमें हिमंत बिस्वा सरमा को हेट स्पीच देने और नागरीकों को कानून हाथ में लेने के लिए उकसाने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कथित हेट स्पीच के लिए सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था।मामले की सुनवाई के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरूण देव चौधरी की बेंच ने कहा कि भारत सरकार, असम राज्य, असम उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को नोटिस जारी किया जाए।

अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा?

सिंघवी ने कहा कि सीएम ने राज्य में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया है, उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि अगर गांधीजी सीएम के बयान को सुनते तो अपनी कब्र में करवटें बदल लेते। हम यह नहीं भूल सकते कि उन्होंने पद की शपथ ली है, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ऐसे भाषण बंद होने चाहिए और मुख्यमंत्री के खिलाफकड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफअपमानजनक टिप्पणियां करते हुए उन्हें 'मिया मुस्लिम' कहा गया।

अब आपकी मंजूरी के बिना मेटा से डेटा शेयर नहीं होगा, व्हाटसएप ने सुप्रीम कोर्ट को दिया आश्वासन

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत में डिजिटल निजता से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई हुई। व्हाट्सऐप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश का पालन करेगा और यूजर्स को अपने डेटा को अन्य मेटा कंपनियों—जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम—के साथ साझा करने पर अधिक नियंत्रण देगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान व्हाट्सऐप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ।

वाराणसी मठ में मनाया गया उत्सव

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक; ब्रह्मचारी को तगड़ा झटका

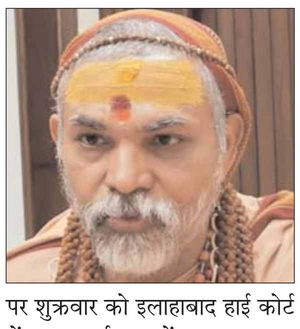

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को राहत देते हुए झूंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज कथित यौन उत्पीड़न के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में मामले में अगली सुनवाई तक जबरदस्ती कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मिली गिरफ्तारी से राहत मिलना, केस दर्ज कराने वाले रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि बटुकों के साथ कथित यौन शौषण के आरोप में शंकराचार्य के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद वाराणसी में मठ में जश्न मनाया गया। शंकराचार्य ने अपने भक्तों और छोटे बच्चों को गुलाल लगाकर इस मौके को उत्सव की तरह मनाया और त्योहार की खुशी में शामिल हुए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती केस में एंटीसिपेटरी बेल पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस हुई। इसमें राज्य सरकार और शिकायतकर्ता के वकीलों ने एंटीसिपेटरी बेल का विरोध किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफसे सीनियर वकीलों ने दलीलें पेश कीं। उनकी तरफ से शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी के क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी दी गई। इस केस में दर्ज स्त्रङ्कभी कोर्ट में पढ़कर सुनाई गई। एक बच्चे के बारे में कहा गया कि मार्कशीट में वह बालिग है। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता की तरफसे हाई कोर्ट में पेश हुए वकील ने एंटीसिपेटरी बेल का विरोध किया। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार में लेटी और इंदरवा में बॉर्डर आउट पोस्ट का उद्घाटन किया, साथ ही एसएसबी के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का ई-उद्घाटन और ई-शिलान्यास भी किया।

नहीं रहे रिंकू सिंह के पिता

लिवर कैंसर के चौथे स्टेज पर हार गए जिंदगी की जंग

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके पिता खानचंद्र सिंह का निधन हो गया। उन्होंने ग्रेटर नोएडा स्थित यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से स्टेज-4 लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। हाल के दिनों में उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। खानचंद्र सिंह कई दिनों से मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी और उन्हें निरंतर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जा रही थी।

शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत

अरविंद को कोर्ट ने किया रिहा,सीबीआई को लगाई फटकार

नई दिल्ली/ एजेंसी

आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में पार्टी के शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में न केवल केजरीवाल और सिसोदिया, बल्कि विजय नायर समेत सभी 23 आरोपियों को भी सभी आरोपों से मुक्त किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सीबीआई इस मामले में किसी भी तरह की 'आपराधिक साजिश' या 'आपराधिक मंशा' को साबित करने में विफल रही। फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने इसे 'सत्य की जीत' बताया और कहा कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसे न्यायपालिका ने विफल कर दिया। इस निर्णय ने आम आदमी पार्टी की साख को मजबूती दी और राजनीतिक माहौल में बड़ी हलचल मचाई। अदालत के फैसले की बाद सीबीआई के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफतुरंत हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है क्योंकि जांच के कई पहलुओं को या तो नज़रअंदाज़ कर दिया गया है या उन पर ठीक से विचार नहीं किया गया है। सीबीआई इस फैसले को तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी। इस मामले में बरी किए गए दूसरे आरोपियों में कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह धाल अर्जुन पांडे, बुचिबाबू गोरंटला, राकेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, चनप्रीत सिंह रायत, अरविंद कुमार सिंह, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी. सरथ चंद्र रेड्डी शामिल हैं। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सीबीआई की जांच की कमियों पर नाराज़गी जताई और कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सिसोदिया के खिलाफ भी कोई पहली नज़र में केस नहीं बनता है। सीबीआई पिछली आप सरकार की एक्साइज पॉलिसी से जुड़े करप्शन केस की जांच कर रही है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सख्त टिप्पणी की कि डिटेल्ड चार्जशीट में कई कमियां थीं।

CMYK

बजट सत्र से पूर्व डॉ. मनीष सिन्हा ने उठाई थी मांग अब छात्रावासों की स्वीकृति से प्रयास सफल

देवभोग। पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए आश्रम एवं छात्रावास निर्माण की मांग को लेकर डॉ. मनीष कुमार सिन्हा द्वारा किया गया प्रयास आखिरकार सफल साबित हुआ है खास बात यह है कि बजट सत्र से पूर्व उन्होंने शासन को इस विषय में अवगत कराया था, जिसका सकारात्मक परिणाम अब राज्य बजट में दिखाई दे रहा है जिला गरियाबंद में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को सुरक्षित आवास और अध्ययन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. सिन्हा ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद को विधिवत मांग पत्र सौंपा था अपने पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि क्षेत्र के अनेक मेधावी विद्यार्थी संसाधनों के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं छात्रावास की कमी के कारण ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों के छात्र-छात्राएं शहरों में रहकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं डॉ. सिन्हा ने बजट सत्र से पूर्व ही इस विषय को शासन के समक्ष गंभीरता से रखा और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आश्रम भवन निर्माण की मांग की उनके इस प्रयास को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए, बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए 200 सीटों का छात्रावास रायपुर में, 100 सीटों का छात्रावास मनेन्द्रगढ़ में तथा 100 सीटों का छात्रावास रायगढ़ में स्वीकृत किया है इसके साथ ही बिलासपुर में 20 करोड़ रुपये की लागत से 'प्रयास' आवासीय विद्यालय को भी मंजूरी दी गई है यह स्वीकृति न केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम भी है इससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सुरक्षित आवास, अध्ययन का अनुकूल वातावरण और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। आने वाले समय में यह सुविधा हजारों विद्यार्थियों के लिए 'गोल्डन पीरियड' सिद्ध हो सकती है डॉ. मनीष सिन्हा ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी, पिछड़ा वर्ग प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद एवं संबंधित जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास की सोच को दर्शाता है और पिछड़ा वर्ग समाज के युवाओं को नई दिशा देगा। समाज के विभिन्न वर्गों ने भी डॉ. मनीष सिन्हा की सक्रिय पहल की सराहना की है। उनका कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि इसी तरह समय रहते मुद्दों को उठाते रहें और बजट सत्र से पूर्व शासन को अवगत कराते रहें, तो क्षेत्र की अनेक ज्वलंत समस्याओं का समाधान संभव है। प्रदेश के लिए यह केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में नई उम्मीद की शुरुआत है – और इस पहल से छेत्र में भाजपा जिला मंत्री डॉ. मनीष सिन्हा की सराहना हो रही है।

उदंती टाइगर रिज़र्व में नन्हे उड़न गिलहरी का सफलतापूर्वक रेस्क्यू

धमतरी। वनमंत्री केदार कश्यप, पीसीसीएफ वन्यप्राणी अरुण पाण्डेय एवं फील्ड डायरेक्टर सतोविशा समाजदार के मार्गदर्शन में उड़न गिलहरी के बच्चे का सफल रेस्क्यू कर उसकी माँ से मिलाया गया। मैनपुर के जर्नलिस्ट हसन खान एवं रक्षापथरा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक धनसिंह नेगी द्वारा 25 फरवरी 2026 को सुबह 11.50 बजे उपनिदेशक कार्यालय को सूचना दी गयी कि गोना जाने वाले मार्ग पर एक सूखा धावड़ा का वृक्ष गिर गया है एवं उस वृक्ष पर एक अज्ञात जानवर उड़न गिलहरी का बच्चा अकेला बैठा है एवं चींटियों द्वारा चोटिल किया जा रहा है। तत्काल उड़न गिलहरी के बच्चे का रेस्क्यू शुरू किया गया। शिक्षको द्वारा बच्चे को स्कूल में छाव में ले जाया गया। तौरेंगा बफर परिक्षेत्र की टीम मौके पर पहुची और उड़न गिलहरी के बच्चे को अपनी कस्टडी में लेकर मौके का मुआयना किया। मौके पर सूखे धावड़ा वृक्ष में उड़न गिलहरी का घोंसला/कोटर पाया गया किन्तु बच्चे की माँ नही मिली। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अभिजीत शर्मा द्वारा दिए गये सुझाव अनुसार उड़न गिलहरी के बच्चे को पीपल, बड़ के फल खिलाये एवं पानी पिलाया गया। चूंकि उड़न गिलहरी निशाचर रात्रि में विचरण करने वाले होते है, इसीलिये शाम होने तक इन्तजार ह्यकिया गया ताकि रात्रि में यदि माँ आसपास होगी तो बच्चे को लेने की संभावना होगी। रेस्क्यू टीम ने शाम होते ही बच्चे को वापस जंगल के पास साजा वृक्ष पर छोड़ दिया और कैमरा ट्रैप बिना फ्लेश लगाया गया और सुरक्षित दूरी से नजर रखी गयी। रात्री लगभग 10 बजे मादा उड़न गिलहरी की हलचल हुई और 2 घंटे में बच्चे को लेकर वापस जंगल की ओर चली गयी। अगले दो दिनों तक टीम आसपास के जंगलो की निगरानी रखेगी ताकि मादा उड़न गिलहरी और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उदंती सीतानदी टाइगर रिज़र्व की टीम, शिक्षको धनसिंह नेगी, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अभिजित शर्मा एवं जर्नलिस्ट हसन खान के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में योगदान के लिए सराहना करती है।

नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर 03 आरोपियों को 09 वर्ष का सश्रम कारावास

धमतरी। धमतरी पुलिस थाना कुरूद द्वारा नशीली दवाओं के अवैध विक्रय के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट प्रकरण क्रमांक 05/2025 में दोषसिद्ध पाते हुए कठोर दंड से दंडित किया गया है। न्यायालय द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 इ के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 09 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है। साथ ही आयुध अधिनियम के अंतर्गत टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड, जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू एवं गुलशन साहू को 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। मुखबिर सूचना पर थाना कुरूद पुलिस ने नया कृषि उपज मंडी के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को होंडा सिटी कार क्रमांक सीजी 04 एएच 6401 सहित गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 288 नग नशीली कैप्सूल , होंडा सिटी कार, 01 देशी कट्टा एवं 05 कारतूस, 02 चाकू, 03 मोबाइल, नगद राशि, कुल 2,65,316 रुपये की संपत्ति जब्त की गई। प्रकरण में अपराध क्रमांक 44/25 धारा 22 ख एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की सुदृढ़ एवं प्रभावी विवेचना के फलस्वरूप आरोपियों को कठोर दंड सुनिश्चित हुआ। उत्कृष्ट विवेचना हेतु विवेचक उप निरीक्षक ईश्वर साकार को पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार द्वारा नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धमतरी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध सतत सख्त कार्यवाही जारी है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

अनाज, फल, सब्जी एवं लघु वनोपज के निर्यात अवसरों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

गरियाबंद। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं एपीडा के संयुक्त तत्वावधान में गत् दिवस जिला पंचायत के सभाकक्ष में अनाज, ताजे फल एवं सब्जियां तथा लघु वनोपज के निर्यात अवसरों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एपीडा से आए प्रतिनिधि द्वारा एपीडा के दायित्वों, निर्यात व्यापार की प्रक्रिया, भारत से वैश्विक स्तर पर निर्यात के अवसर, मुक्त व्यापार समझौते से होने वाले लाभ सहित अन्य विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही निर्यात अनुपालन, जीआई उत्पाद एवं उनके संरक्षण, पैकेजिंग मानक, स्वच्छता तथा एनपीओपी सर्टिफिकेट के संबंध में भी प्रतिभागियों को जानकारी दी गई। इस दौरान कृषि उत्पादों एवं लघु वनोपज के निर्यात को बढ़ावा देना तथा सामुदायिक संगठनों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने हेतु जागरूकता एवं क्षमता संवर्धन विकसित करना था। कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में उत्पादन कर रही स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बेहतर बाजार और सही मूल्य प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उद्योग विभाग के महाप्रबंधक दीनबंधु ध्रुव, बिहान के जिला कार्यक्रम प्रबंधक पतंजल मिश्रा व रमेश वर्मा, एपीडा के प्रतिनिधि आनंद कुमार, प्रदान टीम से ज्योति भूषण तिवारी एवं जय प्रकाश तथा नरेश यादव, कृषि विभाग की एसडीओ सीमा करचाय एवं कृषि विभाग के अन्य प्रतिनिधि, एनआरएलएम द्वारा संचालित एफ्पीओ के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पीजी सदस्य, सीनियर सीआरपी एवं उद्योग सखी उपस्थित रहे।

भाजपा का पं.दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान आज

जिला स्तरीय कार्यशाला होगी आयोजित

धमतरी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन को और अधिक सशक्त एवं कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत धमतरी जिले में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 27 फरवरी 2026 को सुबह 9.30 बजे भाजपा जिला कार्यालय, गोविंद सारंग भवन, विवेकानंद वार्ड क्रमांक 37 धमतरी में आयोजित होगी। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यशाला में जिला पदाधिकारी, जिला कार्यसमिति सदस्य, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, सभी मोर्चा के जिलाध्यक्ष तथा प्रशिक्षण टोली के सदस्य भाग लेंगे। इस कार्यशाला का उद्देश्य संगठन की कार्यप्रणाली, पार्टी की विचारधारा तथा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है, ताकि वे समाज के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकें। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 9.30 बजे जलपान एवं पंजीयन से होगी। इसके बाद उद्घाटन सत्र में अतिथियों का स्वागतए दीप प्रज्वलन, वंदे मातरम् तथा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस अध्यक्षीय संबोधन देंगे। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के विषय में संजय श्रीवास्तव द्वारा विस्तार से जानकारी दी जाएगी। द्वितीय सत्र में प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत मंडल स्तर पर प्रशिक्षण की रूपरेखा, विभिन्न विषयों के लिए वक्ताओं का चयन एवं प्रशिक्षण की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद तृतीय सत्र में आयुष्मान दीक्षित द्वारा पीपीटी के माध्यम से नवाचार विषय पर प्रस्तुति दी जाएगी। चतुर्थ सत्र में नवीन मार्कण्डेय द्वारा पीपीटी पंच परिवर्तन विषय पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यक्रम के समापन सत्र में लता उसेंडी द्वारा जिज्ञासा समाधान एवं समापन उद्बोधन किया जाएगा। भाजपा के इस प्रशिक्षण महाअभियान का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, कार्यपद्धति और जनसेवा के मूल सिद्धांतों से अवगत कराना है, जिससे संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला प्रशिक्षण टोली के सदस्य देवेंद्र दुबे, मनीष देवांगन, हेमंत सेन, अनीश दत्त एवं शुभम जायसवाल से संपर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री से गौसेवा आयोग जिलाध्यक्ष हेमराज सोनी ने की मुलाकात

धमतरी। छत्तीसगढ़ के नये विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष मे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से गौ सेवा आयोग जिलाध्यक्ष हेमराज सोनी ने भेंट की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व सरकार के गौठान को गौ धाम मे रुपांतरित करके प्रदेश मे सभी जिले के विकासखंडो मे सड़को पर घुमंतु गाय, निराश्रित गाय व पशु तस्करी गाय को गौ धाम मे रखकर गौ उत्पाद व जैविक खेती बढावा देने व जन जन तक गौ माता के गौ मूत्र, गोबर व दूध से औषधीय धूप बत्ती, स्वदेशी जैविक खाद निर्माण कर आत्म निर्भर व स्वावलंबी छत्तीसगढ़ बनाने हेतु सरकार ने एक साल पहले गौ धाम निर्माण का निर्णय लिया गया था। पूरे प्रदेश मे गौ सेवा आयोग का जिला व ब्लाक स्तर पर गठन किया गया। गौ सेवा आयोग के जिला व ब्लाक की समिति, जनपद व नगर प्रशासन के बैठक लेकर गौ धाम संचालित हेतु गैर सरकारी संस्था के आवेदन पशु विभाग मे जमा हो चुके। अभी तक गौ धाम संचालन पूरे प्रदेश मे चालू नही हूआ है जिसके कारण आज प्रदेश मे लगातार सड़को पर घुमंतु गाय से दुर्घटना हो रही है। जन व धन हानि हो रही है। साथ मे पशु तस्करी पकड़े गये गायो को भी सिमित गौशाला होने के कारण व्यस्थापन दिक्कत आ रही। इस संबंध में मुख्यमंत्री से भेंट व चर्चा किया व आग्रह किया गया कि जल्द से जल्द गौ धाम योजना संचालित किया जाए जिससे आने वाले दिनो मे दुर्घटनाओ मे अंकुश लगेगी। साथ ही जैविक खाद, गौ उत्पादो के निर्माण होने से छत्तीसगढ़ आत्म निर्भर व विकसित बनेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री, गौ सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष बिसेशर पटेल से चर्चा व जानकारी लेकर जल्द से जल्द गौ धाम सरकार क्रियान्वन करने की बात कही।

तुलसी साहू के शानदार खेल के बदौलत छत्तीसगढ़ की शानदार जीत

बेमेतरा । केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड नई दिल्ली के तत्वधान में नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेस हॉकी प्रतियोगिता 2026 मे छत्तीसगढ़ महिला टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बिहार टीम के खिलाफ की शानदार जीत दर्ज छत्तीसगढ़ महिला टीम का मुकाबला बिहार टीम के साथ हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ टीम ने अपने चिर परिचित खेल का परिचय देते हुए अपने उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए बिहार टीम को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट में धमाकेदार जीत दर्ज की इस शानदार जीत में बेमेतरा जिला अंतर्गत विकासखण्ड बेरला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बारगांव की व्यायाम शिक्षिका तुलसी साहू पूरे मैच में अपने दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ टीम को यादगार विजयी दिलाने में अहम भूमिका निभाई खेल के पहले हाफ में छत्तीसगढ टीम पूरी तरह हावी रही और टीम का पहला गोल मोनिका वैरागडे ने किया सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी तुलसी साहू ने बिहार टीम के अभेद डिफेंस किला को तोड़ते हुए अपना पहला और टीम का दूसरा गोल किया जिससे छत्तीसगढ़ टीम को 2-1 की निर्णायक बढ़त हासिल हुआ। दूसरे हाफ में भी छत्तीसगढ़ टीम ने अपने रणनीति को और मजबूत करते हुए शानदार खेल जारी रखा और माया यादव के शानदार 01 गोल की बदौलत टीम को 3-1 की निर्णायक बढ़त मिली छत्तीसगढ़ टीम की डिफेंस खिलाड़ी रश्मि तिर्की, शोभा वटी,ज्योति तिर्की, भावना गुप्ता,रीठा साहू,सविता चंद्राकर ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने डिफेंस का अभेद किला बनाए रखा जिससे बिहार टीम सिर्फ 01 गोल करने में सफल हो पाई गोल कीपर श्वेता शिंदे ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार की फॉरवर्ड खिलाड़ियों के कड़े प्रहारों को रोकर दर्शकों का दिल जीता।

टीम के सभी खिलाड़ियों ने

जिला प्रेस क्लब बालोद की नई कार्यकारिणी तय, संतोष को फिर अध्यक्ष की कमान और राहुल बनाये गए दोबारा महासचिव

पत्रकार भवन, भूमि आबंटन और एकजुटता पर जोर, हर परिस्थिति में पत्रकारों के साथ खड़ा रहेगा जिला प्रेस क्लब

बालोद । जिला प्रेस क्लब बालोद की अहम बैठक बुधवार को नगर के स्थानीय अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आयोजित हुई। बैठक में संगठन के आगामी तीन वर्षो की दिशा, पत्रकार हितों से जुड़े मुद्दों और कार्यकारिणी के पुनर्गठन पर विस्तार से मंथन किया गया। सर्वसम्मति से संतोष साहू को दूसरी बार अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि राहुल भूतड़ा को पुनः महासचिव चुना गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्तमान कार्यकारिणी को अगले तीन वर्षो तक यथावत रखते हुए आवश्यकता अनुसार विस्तार किया जाएगा। पत्रकारों ने संगठन की मजबूती और एकजुटता पर बल देते हुए स्पष्ट किया कि जिला प्रेस क्लब हर सदस्य के सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी पत्रकार के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में पत्रकार भवन के लिए भूमि आबंटन, भवन निर्माण, पत्रकारों के पंजीयन और जिले भर से आने वाले पत्रकारों के ठहरने की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। अध्यक्ष संतोष साहू और महासचिव राहुल भूतड़ा ने कहा कि पत्रकार भवन के लिए जमीन आबंटन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। साथ ही पत्रकारों की मूलभूत सुविधाओं के लिए ठोस और संगठित प्रयास किए जाएंगे।

प्रेस क्लब को और सशक्त व प्रभावी बनाने का दोहराया गया संकल्प

वरिष्ठ पत्रकार हरबंस अरोरा विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि के रूप में बैठक में शामिल हुए। उन्होंने जिले में पत्रकार भवन निर्माण के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए संगठन को हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, समाचार की अहमियत ही सबसे बड़ी होती है। उन्होंने अध्यक्ष और महासचिव के पिछले कार्यकाल की सराहना करते हुए संगठन की एकता को मजबूती देने की बात कही। वरिष्ठ पत्रकार मोहनदास मानिकपुरी ने भी पत्रकार भवन निर्माण को लक्ष्य बनाकर ठोस पहल करने की आवश्यकता जताई और दोनों पदाधिकारियों को पुनर्नियुक्ति पर बधाई दी। बैठक में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और भिलाई प्रेस क्लब के अध्यक्ष व महासचिव को आमंत्रित सदस्य के रूप में जोड़ने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस दौरान हरबंस अरोरा, संतोष साहू, राहुल भूतड़ा, मोहनदास मानिकपुरी, रवि भूतड़ा, मंजू शर्मा, विवेक वैष्णव, अरुण उपाध्याय, संजय दुबे, बलराम गुप्ता, अफ्जल रिजवी, सतीश रजक, शंकर साहू, संजय सोनी, फुरकान खान, नरेश श्रीवास्तव, किशोर साहू, विकास साहू, लक्ष्मीकांत बंसोड़ ,सुप्रीत शर्मा, जगन्नाथ साहू, देवेंद्र साहू, चिमन पटेल, राजेश साहू, अनीश राजपूत, आरके देवांगन, परसराम साहू, विकास जोशी, राजेश सोनी, राकेश द्विवेदी, जागेश्वर सिन्हा, करण सोनी, ऋषि सिन्हा सहित जिले के विभिन्न संस्थानों के संपादक और ब्यूरो चीफ मौजूद रहे। इस बैठक में जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं संरक्षक ब्रजेश पांडे, ओम टुवानी और ओम गोलछा सहित कुछ अन्य पत्रकार साथी व्यक्ति गत कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सहयोग का संदेश प्रेषित किया। बैठक के अंत में अध्यक्ष और महासचिव ने सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीते तीन वर्षों की तरह आगामी कार्यकाल भी सौहार्द, संवाद और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। प्रेस क्लब को और सशक्त व प्रभावी बनाने का संकल्प दोहराया गया।

स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

बालोद जिले में सभी लोगों को सुगमता से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित कराएंः कलेक्टर दिव्या मिश्रा

बालोद । कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित कराने शासन के विशेष प्राथमिकता में शामिल है। जिसके फ्लस्वरूप जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाकर बालोद जिले में सभी लोगों को सुगमता से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु पुख्ता उपाय सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने बुधवार को संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने विकासखण्डवार स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जेएल उइके, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी समीर पाण्डेय, मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. आरके श्रीमाली, जिला कार्यक्रम प्रबंधक आशुतोष शर्मा के अलावा खण्ड चिकित्सा अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

टीकाकरण के कार्य की स्वास्थ्य केन्द्रवार समीक्षा

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जनसरोकारों से सीधा जुड़ा होता है। इसलिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं त्रुटि की गुजांईश बिल्कुल भी नही होती है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में दिव्या मिश्रा ने जिला अस्पताल बालोद के अलावा जिले के सभी सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्थागत प्रसव की स्थिति की भी बारी-बारी से समीक्षा की। उन्होंने संस्थागत प्रसव में कमी वाले स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारियों से संस्थागत प्रसव की संख्या को बढ़ाने के संबंध में सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गर्भवती माताओं एवं उनके परिजनों को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने टीकाकरण के कार्य की भी स्वास्थ्य केन्द्रवार समीक्षा की।

आम जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश

उन्होंने जिले के अस्पतालों में संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों की भर्ती के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु उन्हें अनिवार्य रूप से पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कराने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को जिला प्रशासन द्वारा गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने हेतु चलाए जा रहे मिशन गोद अभियान में अनिवार्य रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार नवीन स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु तत्काल प्रस्ताव भी भेजने के निर्देश दिए। बैठक में दिव्या मिश्रा ने आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जिले के शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने के अलावा परिवार नियोजन, टीबी एवं मलेरिया उन्मूलन, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आदि कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाकर आम जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

संक्षिप्त समाचार

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मारपीट करने वाले दो युवक पुलिस हिरासत में

रायपुर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में युवक ने प्रेमिका से मिलने के दौरान स्टाफ से मारपीट कर दी। युवक नर्स स्टाफ रूम नंबर 17 पहुंचा। समझाने पर भी नहीं माना और कर्मचारियों से विवाद किया। झगड़ा बढ़ने पर उसने एक कर्मी के हाथ में दांत काट लिया और मारपीट की। स्टाफ ने उसे पकड़कर अस्पताल की पुलिस चैकी पहुंचाया, जहां उसने फिर हाथापाई की। अस्पताल चैकी पुलिस ने युवक और उसके साथी को हिरासत में लिया। दोनों की पहचान बालको चेक पोस्ट निवासी सूरज महंत और अक्षय कुमार के रूप में हुई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को सिविल लाइन थाना लाया गया। वहां उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सह-अधीक्षक रविकांत जाटवर ने बताया कि दो असामाजिक तत्व अस्पताल पहुंचे और एक सफाईकर्मी महिला के साथ विवाद करने लगे। बचाव के दौरान एक स्टाफके हाथ को दांत से काटा गया और मारपीट भी हुई, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है।

नेशनल हाईवे-130 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवारों की मौत

रायपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-130 कटघोरा से अंबिकापुर मार्ग पर कोनकोना पंडो रिसोर्ट के पास की बताई जा रही है, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान एक युवक मलदा निवासी तथा दूसरे की पहचान दामाऊकुंडा निवासी के रूप में की गयी हैं। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण तथा नियमित गश्त की मांग की है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

हैंडपंप मरम्मत से चिरईपानी में लौटा स्वच्छ पेयजल, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

रायपुर। जिले के मनेन्द्रगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिरईपानी के ग्राम चिरईपानी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किए गए हैंडपंप मरम्मत कार्य से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है और लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान हो गया है। बीते कुछ समय से हैंडपंप से गंदा एवं दूषित पानी निकलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के साथ-साथ दैनिक उपयोग के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने त्वरित कार्रवाई की और तकनीकी टीम को मौके पर भेजकर हैंडपंप एवं जल स्रोत की विस्तृत जांच कराई गई। निरीक्षण के दौरान हैंडपंप में तकनीकी खराबी एवं जल स्रोत में गंदगी की स्थिति पाई गई, जिसके बाद विभाग द्वारा तत्काल आवश्यक मरम्मत कार्य कराया गया।

बस्तर की जैव विविधता और लोकसंस्कृति से हुए अभिभूत

पर्यटन विशेषज्ञ किर्सी ने ग्रामीण महिलाओं संग किया महुआ संग्रहण

- संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ ने बस्तर प्रवास के दौरान ग्रामीण पर्यटन, बांस शिल्प और जनजातीय नृत्य पर किया संवाद; बस्तर पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर

रायपुर/ संवाददाता

बस्तर की समृद्ध जैव विविधता, जीवंत लोकसंस्कृति और ग्रामीण जीवन की आत्मीयता ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी गूंज दर्ज कराई है। संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय पर्यटन विशेषज्ञ एवं 'हिवा कोचिंग एंड कंसल्टिंग' की संस्थापक सुश्री किर्सी ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान ग्रामीण परिवेश को नजदीक से समझते हुए स्थानीय महिलाओं के साथ महुआ संग्रहण में सहभागिता की। प्रवास के तीसरे दिन उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के बीच 'नेचर एंड एनवायरमेंट ऑब्जर्वेशन वॉक' और बर्ड वॉचिंग गतिविधियों से दिन की शुरुआत की। स्थानीय गाइडों के साथ जंगल की पगडंडियों पर चलते हुए उन्होंने बस्तर की जैव विविधता, वन संपदा और पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं को समझा। ग्रामीण महिलाओं के साथ महुआ संग्रहण करते हुए वे खासा उत्साहित दिखीं और इसे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त उदाहरण बताया। दोपहर के समय बस्तर की सांस्कृतिक विरासत का मनोहारी दृश्य तब सामने आया, जब धुरवा जनजातीय नृत्य दल ने पारंपरिक मंडरी, डंडारी और गुरगाल नाचा की आकर्षक प्रस्तुति दी। पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों की थाप पर प्रस्तुत इन लोकनृत्यों ने विदेशी अतिथि को मंत्रमुग्ध कर दिया। पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों ने उन्हें इन नृत्यों के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। इसके पश्चात उन्होंने पर्यटन विक्रेताओं, स्थानीय हितधारकों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण संवाद किया। इस

दौरान बस्तर में ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं, उत्पादों के परिष्करण, विपणन रणनीतियों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकास पर तकनीकी चर्चा हुई। धुरमारास क्षेत्र में स्थानीय बांस शिल्पियों और कारीगरों के साथ आयोजित 'तकनीकी इंटरैक्शन' सत्र में सुश्री किर्सी ने बस्तर के प्रसिद्ध बांस हस्तशिल्प की बारीकियों को समझा और उत्पादों के गुणवत्ता संवर्धन एवं वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने के सुझाव दिए। उन्होंने 'कल्चर वॉक' के माध्यम से ग्रामीण जीवन के विविध आयामों का अनुभव किया और स्थानीय आतिथ्य की सराहना की। दिन का समापन धुरवा डेरा होमस्टे में आयोजित डिब्रीफ सत्र के साथ हुआ, जहां पूरे दिन की गतिविधियों की समीक्षा की गई। जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस प्रवास का उद्देश्य बस्तर के ग्रामीण पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर सशक्त रूप से स्थापित करना है। विशेषज्ञ ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बस्तर में प्रकृति, संस्कृति और सामुदायिक सहभागिता का अद्भुत समन्वय है। यदि इसे सुनियोजित रूप से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाए, तो यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का आकर्षक केंद्र बन सकता है। बस्तर का यह प्रवास न केवल सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम बना, बल्कि ग्रामीण महिलाओं, कारीगरों और स्थानीय समुदाय के आत्मविश्वास को भी नई ऊर्जा देने वाला साबित हुआ।

चोरी के आरोप में नाबालिग की पिटाई

रायपुर। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत कमल विहार पुलिस सहायता केंद्र में पदस्थ दो आरक्षकों द्वारा मोबाइल चोरी के शक में एक नाबालिग की कथित रूप से बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। नाबालिग के शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार, कमल विहार पुलिस सहायता केंद्र में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 1211 लक्ष्मी नारायण एवं आरक्षक क्रमांक 2382 आसमान सिंह ने ड्यूटी के दौरान चौकी प्रभारी को बिना सूचित किए दूसरी जगह जाकर एक नाबालिग को मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ा। बताया जाता है कि दोनों आरक्षकों ने पूछताछ के दौरान नाबालिग को बुरी तरह पीटा। पिटाई से नाबालिग के शरीर के अन्य हिस्सों पर स्पष्ट चोट के निशान उभर आए। घटना की जानकारी सामने आते ही पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। डीसीपी वेस्ट जोन संदीप पटेल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दोनों आरक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच में प्रथम दृष्टया आमजन के साथ दुर्व्यवहार, चौकी प्रभारी के आदेशों की अवहेलना तथा ड्यूटी के दौरान स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करने के तथ्य सामने आने पर दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। डीसीपी संदीप पटेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान आरक्षक लक्ष्मी नारायण और आसमान सिंह को रक्षित केंद्र रायपुर संबद्ध किया गया है।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने पीएम सूर्यघर योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की

- जन-जागरूकता बढ़ाएं व लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें

रायपुर। संवाददाता

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा हेतु आज जिला रायपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधि, विद्युत विभाग, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत प्रकरणों, सब्सिडी की स्थिति तथा स्थापित सोलर रूफ्टॉप सिस्टम की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश देते हुए सभी बैंकों एवं संबंधित विभागों को स्व-स्रोत आवेदनों की संख्या बढ़ाने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने सभी बैंक वार लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पात्र हितग्राहियों को ऋण देने में विलंब न करें तथा एसबीआई को नाराजगी जाहिर करते हुए कहां की इस योजना को गंभीरता से लें एवं हितग्राहियों को योजना की जानकारी प्रदान करें। कलेक्टर ने आम नागरिकों को योजना का अधिकतम लाभ प्रदान करने हेतु व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने, शिविरों का आयोजन करने तथा ग्राम एवं वार्ड स्तर पर प्रभावी प्रचार-प्रसार करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि तकनीकी स्वीकृति, ऋण स्वीकृति एवं सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो और सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सभी बैंक एवं संबंधित विभाग अपनी साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें।

समूह की महिलाएं कर रही है प्राकृतिक गुलाल रंग का निर्माण........

- इस बार प्राकृतिक रंगों से रंगीन होगी होली
- स्व सहायता समूह की महिलाएं कर रही है प्राकृतिक गुलाल का निर्माण

रायपुर/ संवाददाता

रंगों के त्योहार होली को स्वसहायता समूह की महिलाएं इस बार और खास बना रही है। होली के त्योहार को प्राकृतिक रंगों से मनाने के लिए महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही है। गरियाबंद जिले के ग्राम सढ़ौली की राखी महिला ग्राम संगठन की 10 सक्रिय महिलाएँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत हर्बल गुलाल का निर्माण कर आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की मिसाल पेश कर रही हैं। समूह की महिलाएं पलाश से पीला, चुंकदर से लाल और पालक के पत्तों से हरा रंग निकालकर मक्के की सूखी डंठल से प्राप्त अरारोट पाउडर में मिलाकर प्राकृतिक गुलाल का निर्माण कर रही है। इसमें हानिकारक रसायनिक तत्वों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता। जिससे हर्बल गुलाल त्वचा एवं सेहत के लिए सुरक्षित रहता है। राखी महिला ग्राम संगठन की ये महिलाएँ न केवल होली के त्योहार को प्राकृतिक और सुरक्षित बना रही हैं, बल्कि अपनी आजीविका को भी मजबूत कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएँ आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की नई कहानी लिख रही हैं। यह पहल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इन महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज महिलाएं स्वरोजगार सृजित कर आत्मनिर्भर बन रही है और समाज में अपनी अलग पहचान बना रही है। पीआरपी मीना साहू ने बताया कि पिछले वर्ष भी बिहान समुह के दीदियों द्वारा कुल 30 हजार रूपये से अधिक की बिक्री कर लगभग 10 हजार रूपये से अधिक की शुद्ध मुनाफा अर्जित की थी। समूह की महिलाओं से चर्चा के फलस्वरूप पारंपरिक तरीकों से बनाए गए प्राकृतिक गुलाल से न केवल सेहत स्वस्थ रहेगा, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल रहेगा। साथ ही महिलाओं के लिए आमदनी का नया स्रोत भी बन रहा है।

कांग्रेस का नग्न प्रदर्शन विकास विरोधी मानसिकता का परिचायक

- विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयास के लिए कांग्रेस आलाकमान देश से माफी मांगे

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पाण्डेय ने नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक 'एआई समिट' के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अभद्र और अमर्यादित प्रदर्शन पर कड़ा प्रहार किया है। श्रीमती शताब्दी पाण्डेय ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान और अद्यतन विकास के गौरव को शर्मसार करने वाली घटना बताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि जहाँ आज पूरी दुनिया भारत की तकनीकी शक्ति का लोहा मान रही है और नई दिल्ली 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रही है, वहीं कांग्रेस का यह 'नग्न प्रदर्शन' उसकी पिछड़ी और विकास-विरोधी सोच को दर्शाता है। राजनीति में विरोध के कई सभ्य तरीके होते हैं, लेकिन सड़कों पर उतरकर इस तरह का अश्लील आचरण करना कांग्रेस के राजनीतिक दीवालिएपन और वैचारिक पतन की पराकाष्ठा है। यह न केवल भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, बल्कि विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास भी है। कांग्रेस आलाकमान को इस अमर्यादित कृत्य के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि एआई समिट युवाओं के लिए रोजगार और नवाचार के नए द्वार खोल रहा है। कांग्रेस इसका विरोध कर सीधे तौर पर देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस हमेशा से नई तकनीकों का विरोध करती आई है।

मुख्य मार्ग के किनारे से हटाये गये अवैध कब्जे

रायपुर। पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) मयंक गुर्जर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम, सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा, सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) रमेश येरेवार, थाना उरला पुलिस बल तथा नगर निगम बीरगांव के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त उपस्थिति में आज दिनांक 25.02.2026 को थाना उरला क्षेत्रांतर्गत बीरगांव नगर निगम मुख्य मार्ग के किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। संयुक्त कार्यवाही के दौरान सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से संचालित दुकानों, ठेलों, गुमटियों एवं अन्य अस्थायी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कई स्थानों पर सड़क एवं फुटपाथ पर अवैध कब्जा कर आवागमन में बाधा उत्पन्न की जा रही थी, जिससे आम नागरिकों तथा वाहन चालकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कार्यवाही के दौरान संबंधित संचालकों को समझाइश भी दी गई कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण न करें तथा निर्धारित स्थानों पर ही अपना व्यवसाय संचालित करें। पुलिस एवं नगर निगम की टीम द्वारा मौके पर आवश्यकतानुसार बल प्रयोग किए बिना सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही संपन्न की गई। इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप मुख्य मार्ग पर यातायात का संचालन पुनः सुचारु एवं व्यवस्थित हो सका है। आम नागरिकों को आवागमन में हो रही असुविधा से राहत मिली है ।

हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं पर अर्धदिवसीय सेमिनार आयोजित

ऊर्जा विभाग सचिव ने छत्तीसगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन की संभावनाओं पर की चर्चा

- राज्य में स्टील एवं स्पंज आयरन उद्योग का मजबूत आधार रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे उरला, सिलतरा, भिलाई तथा रायगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में है

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) द्वारा आज छत्तीसगढ़ को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्लोबल क्लीन एनर्जी के विस्तार के उद्देश्य से अर्धदिवसीय सेमिनार का आयोजन कोर्टयार्ड बाय मैरियट में किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग के सचिव श्री रोहित यादव (आईएएस) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सचिव श्री रोहित यादव ने कहा कि सेमिनार का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक परिवेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना तथा पारंपरिक औद्योगिक ईंधनों के स्थान पर स्वच्छ विकल्पों को अपनाने की दिशा में कार्य करना है। उन्होंने बताया कि बायोमास आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए इसे प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकेगी। सेमिनार में चर्चा के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ में कृषि अवशेष, डेयरी उद्योग से उत्पन्न अपशिष्ट, फल एवं सब्जी मंडियों का जैविक कचरा तथा गोबर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उपयुक्त तकनीक के माध्यम से इनके प्रसंस्करण द्वारा बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं। राज्य में स्टील एवं स्पंज आयरन उद्योग का मजबूत आधार रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे उरला, सिलतरा, भिलाई तथा रायगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में है। इसके अतिरिक्त जगदलपुर एवं बस्तर में भी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं। इन क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन को औद्योगिक ईंधन के रूप में

अपनाने से दोहरे लाभ होंगे—एक ओर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं बायोमास के मूल्य संवर्धन से किसानों की आय में वृद्धि होगी। यह पहल भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अपशिष्ट से आय सृजन तथा नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगी। ऊर्जा विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमित सरकार ने कहा कि सेमिनार का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक इकोसिस्टम में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना, भविष्य के अनुसंधान की दिशा तय करना, संभावित बाधाओं की पहचान करना तथा इसके व्यापक क्रियान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। सेमिनार में उपस्थित विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए। ॥4स्रह्म्श्दद्गठ्ठ EconomyÑ Innovation-Led Growth in Industrial Clusters in Chhattisgarh विषय पर भाभा परमाणु अनुसंधान रिसर्च संस्थान (बार्क) के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री सयाजी मैहत्रे ने बायोमास आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर प्रस्तुतीकरण दिया। Accelerating Green Hydrogen Adoption in Chhattisgarh विषय पर Ministry of New and Renewable Energy, भारत सरकार के विषय विशेषज्ञ श्री धर्मेन्द्र कुमार पंचार्या, भिलाई स्टील प्लांट के प्रतिनिधियों एवं अन्य उद्यमियों ने पैनल चर्चा में भाग लिया। सेमिनार में वित्तीय संस्थानों जैसे एसबीआई एवं नाबार्ड के प्रतिनिधियों की भी सहभागिता रही। इसके अतिरिक्त नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से डॉ. धर्मेन्द्र कुमार, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. सचिन कुमार, बार्क, सीएसएमसीआरआई भावनगर, आईआईटी भिलाई के वरिष्ठ वैज्ञानिक, विभिन्न निजी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि तथा सीबीडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकीय

मोतियाबिंद शिविर बना त्रासदी ?

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्वास्थ्य शिविर में मोतियाबिंद के आपरेशन के बाद संक्रमण से नौ मरीजों की एक आंख निकालनी पड़ी और नौ अन्य की एक आंख की रोशनी चली गई। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस शिविर का आयोजन एक स्थानीय निजी अस्पताल की ओर से किया गया था और यहां कई लोगों ने 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत आंख के आपरेशन कराए। प्रारंभिक जांच-पड़ताल के बाद स्थानीय प्रशासन ने माना कि इन मामलों में गंभीर चूक हुई है।सामान्यतः चिकित्सक मरीज के मर्ज को ठीक कर उसके जीवन को बेहतर बनाता है, इसलिए उसे ईश्वर का दूसरा रूप भी कहा जाता है। ऐसे में किसी चिकित्सक या उनके सहायक की इस तरह की लापरवाही को किस तरह देखा जाएगा। यह घटना इस बात को भी उजागर करती है कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अमले में कर्तव्य के प्रति कोताही और असंवेदनशीलता की जड़ें किस तरह गहरी होती जा रही हैं।यह घटना कोई पहला मामला नहीं है। मोतियाबिंद के आपरेशन के बाद संक्रमण से आंखों की रोशनी खत्म हो जाने के मामले देश भर में अक्सर सामने आते रहते हैं। चाहे सरकारी अस्पताल हों या निजी, इस तरह की लापरवाही अब आम बात हो गई है। गोरखपुर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में करीब तीस मरीजों की आंख का आपरेशन किया गया था, जिसके बाद चौबीस घंटे के भीतर अठारह मरीजों की आंख में संक्रमण हो गया। सवाल है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है?हालांकि ऐसे मामलों में स्पष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन साफ है कि उन पर कड़ाई से अमल नहीं हो पा रहा है। अक्सर देखा गया है कि इस तरह की घटनाओं में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित के जख्मों पर मामूली मुआवजे का मरहम लगाकर मामले को निपटा दिया जाता है, जिस कारण व्यवस्था में कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आलम जस का तस बना रहता है। जाहिर है, जब तक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।खूबसूरत दुनिया की सुंदरता देखने के लिए आंखों की रोशनी बहुत ही अनमोल है, जिसे बुढ़ापे तक सुरक्षित रखना जरूरी है। हमारे शरीर के सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी अगर शरीर के सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण अंग की बात करें, तो वह आंखें होती हैं। हम अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण हमारी आंखों की रोशनी कम होने के साथ-साथ गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाती है। इसमें मोतियाबिंद बहुत आम समस्या है।

आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई कई रूपों में दिखाई देती है। एक ओर तकनीकी क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक श्रम-आधारित रोजगार असुरक्षित होते जा रहे हैं। डिजिटल विभाजन नई सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज के समय में केवल असमानताओं पर प्रहार एवं समानता के विस्तार की एक सार्थक पुकार का अंतरराष्ट्रीय आयोजन ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का आह्वान है। वर्ष 2026 में यह दिवस विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि विश्व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी संक्रमण, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच नई संतुलित व्यवस्था की तलाश में है। इस वर्ष की थीम समावेश को सशक्त बनानाः सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी हो और समावेशन तभी प्रभावी है जब वह न्यायपूर्ण हो।

असमानताओं पर प्रहार, समानता का विस्तारः एक सार्थक पुकार

(ललित गर्ग)

सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अवसरों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था की स्थापना का आग्रह करता है जिसमें संसाधनों, अधिकारों और गरिमा का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की समान उपलब्धता नहीं मिलती, तब तक प्रगति अधूरी है। 2026 की थीम विशेष रूप से उन समुदायों की भागीदारी पर बल देती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं-चाहे वे आर्थिक रूप से वंचित हों, सामाजिक रूप से उपेक्षित हों या राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से दूर हों। समावेशन का सशक्तिकरण केवल नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अधिकार है।

आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई कई रूपों में दिखाई देती है। एक ओर तकनीकी क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक श्रम-आधारित रोजगार असुरक्षित होते जा रहे हैं। डिजिटल विभाजन नई सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। ग्रामीण और शहरी, विकसित और विकासशील, पुरुष और महिला, सक्षम और दिव्यांग-इन सबके बीच संसाधनों की असमान पहुंच सामाजिक तनाव को जन्म देती है। ऐसे समय में सामाजिक न्याय का अर्थ है इन अंतरों को पहचानना और उन्हें पाटने के लिए लक्षित, संवेदनशील और पारदर्शी नीतियों का निर्माण करना। सम्मानजनक कार्य की अवधारणा भी सामाजिक न्याय के केंद्र में है। केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा कार्य-संस्कृति बनाना आवश्यक है जिसमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। आर्थिक विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह मानव गरिमा के साथ जुड़ा हो। यदि विकास केवल आंकड़ों में सीमित रह जाए और आम नागरिक के जीवन में राहत न ला सके, तो वह विकास नहीं, केवल विस्तार है।

मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र इस युग की अनिवार्यता बन चुका है। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि संकट किसी भी समाज को अचानक अस्थिर कर सकता है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धजन, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक-इन सभी के लिए संरक्षित ढांचा ही न्यायपूर्ण समाज की नींव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का विचार ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। आज भी सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक पूर्वाग्रहों, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक असमानताओं से भी जुड़ा है।

समकालीन भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग,

दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और नशा-पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि सामाजिक न्याय विभाजन की राजनीति नहीं, बल्कि समावेशन की नीति के माध्यम से स्थापित हो। संतुष्टिकरण बनाम तुष्टिकरण की अवधारणा इसी दिशा में एक वैचारिक संकेत है, जो समाज को जोड़ने की बात करती है। फिर भी चुनौतियां शेष हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती जीवन-यापन लागत आम नागरिक के लिए वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि जनसंतोष और जनकल्याण सुनिश्चित करना है। यदि नागरिक स्वयं को असुरक्षित, असमान या उपेक्षित अनुभव करें, तो सामाजिक न्याय का आदर्श खोखला प्रतीत होने लगता है।

आज आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व के रूप में देखा जाए। हमने आचरण की पवित्रता एवं पारदर्शिता की बजाय कदाचरण एवं अनैतिकता की कालिमा का लोकतंत्र बना रखा है। ऐसा लगता है कि धनतंत्र एवं सत्तातंत्र ने जनतंत्र को बंदी बना रखा है। हमारी न्याय-व्यवस्था कितनी भी निष्पक्ष, भव्य और प्रभावी हो, फ्रांसिस बेकन ने ठीक कहा था कि 'यह ऐसी न्याय-व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की यंत्रणा के लिये दस अपराधी दोषमुक्त और रिहा हो सकते हैं।' रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था कि 'मनुष्य का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है।' लेकिन हमारे देश के कानून एवं शासन व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता, आम आदमी सजा का जीवन जीने को विवश है। सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक एकता भंग नहीं की जा सकती। शासन और प्रशासन की प्रत्येक नीति का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। यदि शक्ति के स्रोत जनहित में प्रयुक्त न हों, तो वे असंतोष और अविश्वास को जन्म देते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। क्या हमारा लोकतंत्र समानता का लोकतंत्र है या विभेद का? क्या हमारी स्वतंत्रता सबके लिए समान अवसर लेकर आई है या केवल कुछ वर्गों तक सीमित है? क्या हमारी नीतियां पारदर्शिता और नैतिकता पर आधारित हैं या वे जटिलता और असमानता को बढ़ा रही हैं? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोजना ही इस दिवस की सार्थकता है। सामाजिक न्याय केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेद से ऊपर उठकर यदि नागरिक परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, तो सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ किया जा सकता है। शिक्षा संस्थान, नागरिक संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच-सभी को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा और डिजिटल नवाचार नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन अवसरों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। अन्यथा विकास की गाड़ी कुछ लोगों को आगे ले जाएगी और शेष को पीछे छोड़ देगी। समावेशन का सशक्तिकरण इसी असंतुलन को रोकने का प्रयास है। प्रतिदिन कोई न कोई कारण महंगाई को बढ़ाकर हम सबको और धक्का लगा जाता है और कोई न कोई टैक्स, अधिभार हमारी आय को और संकुचित कर जाता है। जानलेवा प्रदूषण ने लोगों की सांसों को बाधित कर दिया, लेकिन हम किसी सम्यक् समाधान की बजाय नये नियम एवं कानून थोप कर जीवन को अधिक जटिल बना रहे हैं। सामाजिक न्याय व्यवस्था तभी सार्थक है जब आम जनता निष्कंटक एवं समस्यामुक्त समानता का जीवन जी सके। 2026 का यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि न्याय और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग सामाजिक न्याय से होकर ही गुजरता है। यदि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ जीवन जी सके, तभी हम कह सकेंगे कि हमने सामाजिक न्याय के आदर्श को साकार किया है। इस तरह सामाजिक न्याय केवल नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि चेतना का प्रश्न है। यह हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों में परिलक्षित होना चाहिए। जब नागरिक और शासन दोनों मिलकर समानता, गरिमा और अवसर की संस्कृति का निर्माण करेंगे, तभी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। समावेश को सशक्त बनाकर और असमानताओं की खाई को पाटकर ही हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, अधिक मानवीय और अधिक स्थायी हो।लेखक, पत्रकार, स्तंभकार। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

क्या है पैक्स सिलिका ? इसमें शामिल होकर भारत ने कैसे चीन को बेचैन कर दिया है?

(नीरज कुमार दुबे)

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में दीर्घकालिक चक्रवृद्धि विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यह सोच 1947 से निरंतर बनी रहती तो आज स्थिति अलग होती, लेकिन अब भी शुरुआत होने पर अगली पीढ़ियां इसका लाभ उठाएंगी।

भारत ने आज अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पैक्स सिलिका से औपचारिक रूप से जुड़ते हुए एक अहम रणनीतिक कदम उठाया। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर दोनों देशों ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भरोसेमंद और लचीला सहयोग तंत्र विकसित करना है। हम आपको बता दें कि पैक्स सिलिका अमेरिकी विदेश विभाग का प्रमुख ढांचा है, जिसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में भरोसेमंद साझेदारों का नेटवर्क बनाना है। घोषणा पत्र में आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को दीर्घकालिक वैश्विक समृद्धि का परिवर्तनकारी साधन बताया गया है।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में दीर्घकालिक चक्रवृद्धि विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यह सोच 1947 से निरंतर बनी रहती तो आज स्थिति अलग होती, लेकिन अब भी शुरुआत होने पर अगली पीढ़ियां इसका लाभ उठाएंगी। वैष्णव ने बताया कि भारतीय इंजीनियर उन्नत दो नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम कर रहे हैं। वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को लगभग दस लाख अतिरिक्त कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी और भारत इस प्रतिभा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र बन सकता है। छात्रों को विश्वस्तरीय चिप डिजाइन उपकरण निशुल्क उपलब्ध कराए जाने की बात भी उन्होंने कही।

इस अवसर पर बोलते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसे वैश्विक प्रौद्योगिकी व्यवस्था में एक निर्णायक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि भारत का संकल्प और आत्मनिर्भर मार्ग चुनने की इच्छा इस साझेदारी को विशिष्ट बनाती है। व्यापार समझौते से लेकर रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग तक दोनों देशों के बीच असीम संभावनाएं हैं।

अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप सचिव जैकब हेलबर्ग ने इसे भू राजनीतिक संदर्भ में रखा। उन्होंने कहा कि यह पहल हथियारबंद निर्भरता और दबाव आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं को अस्वीकार करने का संदेश है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुरक्षा को राष्टीय सुरक्षा की तरह देखा जाना चाहिए। साथ ही, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के संदर्भ में यह साझेदारी भारत को आर्थिक और तकनीकी आधार प्रदान करेगी, जिससे वह अपने सामरिक हितों की रक्षा कर सके। आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने की अमेरिकी सोच भारत के लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक युद्ध और भू राजनीति में डिजिटल अवसंरचना और डेटा केंद्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पारंपरिक सैन्य साधन। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण अत्यधिक पूंजी और तकनीकी परिशुद्धता मांगता है। यदि भारत को वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य पाना है तो उसे नीतिगत स्थिरता, अनुसंधान निवेश और कौशल विकास पर निरंतर ध्यान देना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी एक ध्रुव पर अत्यधिक निर्भर न हो। बहरहाल, पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी एक अवसर है, जिससे वह 21वीं सदी की तकनीकी व्यवस्था में सक्रिय निर्माता की भूमिका निभा सकता है। यह कदम भारत को केवल बाजार नहीं, बल्कि मानक निर्धारक और आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में है। यदि इस पहल को दीर्घकालिक रणनीति और घरेलू सुधारों के साथ जोड़ा गया, तो आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक और सामरिक स्थिति कहीं अधिक सुदृढ़ हो सकती है।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

देशों की आर्थिक दशा बदलती एआई

नई दिल्ली में चल रहा 'एआई इम्पैक्ट समिट' अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था पर एआई के बढ़ते प्रभाव पर हुई चर्चाएं अहम हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अब इस नई तकनीक से प्रभावित होने लगी हैं। यह कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, क्योंकि एआई एक क्रांतिकारी तकनीक है। इससे पहले जो भी तकनीकी बदलाव हुए हैं, उन्होंने कमोबेश शारीरिक श्रम पर असर डाला था। उनसे हमारे भौतिक कामकाज प्रभावित हुए थे, पर एआई कुशल कामगारों को प्रभावित कर रही है। एआई समिट में यह भी चर्चा हुई कि इससे लोगों की उत्पादकता कितनी बढ़ रही है और उनके काम करने के तरीके कितने बदल रहे हैं।

(अरुण कुमार)

यह बदलाव काफी तेजी से हो रहा है, क्योंकि एआई में निवेश काफी ज्यादा हो रहा है। मसलन, पिछले साल जनवरी में दूसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एआई के बुनियादी ढांचे को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए लगभग 500 अरब डॉलर तक के निवेश की घोषणा की। वहां 'मेटा' जैसी बड़ी कंपनियां भी अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। चीन भी इस तरह के कामों में पीछे नहीं है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जो देश एआई में सर्वोच्चता हासिल कर लेगा, वह विश्व-व्यवस्था पर अपना नियंत्रण बना लेगा।

यही वजह है कि एआई को 'पब्लिक गुड्स' के रूप में विकसित करने की वकालत की जाती है, ताकि यह सबको सुलभ हो और सभी इसका इस्तेमाल कर सकें। यह मांग इसलिए भी हो रही है, क्योंकि एआई से अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। यह किसी उद्योग के लिए जरूरी शोध कर सकती है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर तत्काल बता सकती है कि कहां उसके लिए बेहतर कच्चा माल उपलब्ध है और कहां से उसे लाना तुलनात्मक रूप से आसान होगा। इसी तरह, मार्केटिंग की रिपोर्ट तैयार करने में भी एआई से काफी मदद मिलती है। कहां और किस क्षेत्र में कैसी मांग है, इससे यह पता करना आसान हो जाता है। यानी, सूचनाएं उपलब्ध रहने से तमाम उद्यमों की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। इस तरह उनकी उत्पादन लागत कम हो सकती है।

इसी तरह, नए-नए शोध में एआई से फायदा मिल सकता है। मिसाल के लिए, अब प्रोटीन की संरचना समझने के लिए 'अल्फाफोल्ड' सॉफ्टवेयर की मदद ली जाने लगी है। यह प्रोटीन की थ्रीडी संरचना बना देती है, वह भी थोक के भाव से। पहले प्रोटीन की एक संरचना के विश्लेषण के लिए एक शोध-कार्य होते थे, लेकिन 'अल्फाफोल्ड' हजार शोध के बराबर काम करने में सक्षम है। इससे दवाओं के निर्माण में फायदा होता है। इस जैसे तमाम पेशेवर कामों में अब एआई की भागीदारी संभव होगी। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम किसी डॉक्टर या सीए के इंटर्न के रूप में किसी एआई मॉडल को सेवा देते देखें।

एआई भाषायी बाधाओं को दूर करके अर्थव्यवस्था को मदद कर सकती है। अभी सुदूर देशों के साथ संपर्क साधना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उद्यमी भाषायी तौर पर कुशल नहीं होते, लेकिन एआई द्वारा आसानी से मूल भाषा में अनुवाद करके सामग्री उपलब्ध कराने में उन्हें मदद मिल सकती है। इससे नई-नई चीजों के ईजाद में काफी सहायता मिलेगी और कामकाज में तेजी आ सकेगी।

जीवन-स्तर की गुणवत्ता में एआई द्वारा सुधार लाना आर्थिक नजरिये से सुखद माना जाता है। एआई पेशेवर लोगों की क्षमता बढ़ाने में मददगार होगी। इससे उनके जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा और सूचनाएं न सिर्फ काफी तेजी से आ सकेंगी, बल्कि उनका गहन विश्लेषण भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। इससे कर्मियों की क्षमताओं में इजाफा होगा। वित्तीय बाजार पर भी इसका खासा असर पड़ेगा और वित्तीय योजनाएं बनाने में एआई पेशेवरों की मदद कर सकेगी।

हालांकि, इसकी राह में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिस पर हमें कहीं अधिक संजीदगी से काम करना होगा। जैसे, सन माइक्रोसिस्टम्स के संस्थापक विनोद खोसला ने एआई समिट में बताया कि एआई की वजह से पारंपरिक रोजगार प्रभावित हो सकते हैं और 2030 तक कॉल सेंटर व बीपीओ जैसे कामों में लोगों की जरूरतें खत्म हो सकती हैं। जाहिर है, अब काम करने के तरीके बदल रहे हैं और उसी बदलाव के अनुसार हमें लोगों की जरूरतें भी पूरी करनी होंगी। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत में महत्वाकांक्षी नौजवानों की संख्या दुनिया

में सबसे अधिक है।

एआई से कुछ क्षेत्रों में नए रोजगार का सृजन भी होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में शुरुआती दौर में मांग घट सकती है, जिसके लिए हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छी शिक्षा और कौशल जिनके पास होगा, वे आगे बढ़ जाएंगे। यही कारण है कि एआई में अमेरिका और चीन की तेजी को बाकी दुनिया के लिए खतरा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे देशों के बीच ठीक उसी तरह असमानता बढ़ सकती है, जिस तरह समाज में कुशल और अकुशल लोगों के बीच गैर-बराबरी है। आशंकाएं इस बात की भी हैं कि एआई-सक्षम देश नव-साम्राज्यवादी ताकत बन सकती हैं और वे उन मुल्कों पर दबाव बना सकती हैं, जो एआई अपनाने में कमजोर रहेंगी। इससे दुनिया में आर्थिक विषमता का एक नया चक्र शुरू हो सकता है।

अच्छी बात है कि एआई से अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए भारत जैसे देश लगातार काम कर रहे हैं। हमें कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसमें सबसे पहला है, शोध कार्यों के लिए माहौल सुधारना। इसके लिए उच्च शिक्षण व शोध संस्थानों को पहल करनी चाहिए और शोध-संबंधी माहौल की जो कमियां हैं, उनको दूर करने के प्रयास करने चाहिए। सरकारों को भी शोध व विकास पर अपने खर्च बढ़ाने होंगे। दूसरा काम शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है। बेशक, नई शिक्षा नीति में यह प्रयास किया गया है कि छोटे-छोटे बच्चे भी नई-नई तकनीक को समझ सकें, लेकिन कक्षा के मुताबिक उनकी मानसिक क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जरूरी है। 'कैसे हमें सीखना चाहिए' यह सीख हमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के बच्चों को सिखानी होगी। अच्छा होगा, भारत यह पहल करे कि 'ग्लोबल साउथ' के देश आपस में मिलकर एआई पर काम करेंल्ह। इससे एआई का हर मोर्चे पर अधिकतम फायदा उठाया जा सकेगा। (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री है)।(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मरारपारा की जर्जर कच्ची आंगनबाड़ी बनी खतरे का घर

बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़, विभागीय लापरवाही पर सवाल

कोण्डागांव। जिला मुख्यालय के मरारपारा में एक आंगनबाड़ी केंद्र किराए के जर्जर कच्चे मकान में संचालित हो रही है, जो नन्हे बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। जिला मुख्यालय अंतर्गत इस क्षेत्र में लंबे समय से दर्जनभर से अधिक बच्चे इसी असुरक्षित भवन में शिक्षा और पोषण सेवाएं लेने को मजबूर हैं। बारिश और मौसम के बदलते हालातों में यह कच्चा मकान कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। केंद्र की सहायिका और कार्यकर्ता के अनुसार, इस जर्जर भवन की जानकारी संबंधित विभाग को पहले ही दी जा चुकी है, बावजूद इसके अब तक किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था या वैकल्पिक भवन की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे पालकों में गहरी चिंता बनी हुई है और वे अपने बच्चों के भविष्य और सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। सूत्रों के मुताबिक, आंगनबाड़ी केंद्र में पदस्थ कार्यकर्ता के कार्य को लेकर भी लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि वे कई बार कार्य के दौरान केंद्र से अनुपस्थित रहती हैं, जिससे बच्चों को सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाली प्रारंभिक शिक्षा और पोषण सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय नागरिकों और पालकों ने प्रशासन व महिला एवं बाल विकास विभाग से मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द सुरक्षित भवन की व्यवस्था की जाए और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई हो, ताकि नन्हे बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। यह मामला केवल एक आंगनबाड़ी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है, जहां बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई मुददा नहीं होना चाहिए। रेणु प्रकाश जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग बताया कि जिले में कुल 1834 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे है। जिसमें 335 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में संचालित किया जा रहा है। व 102 आंगनबाड़ी केंद्र अति जर्जर अवस्था में जिन्हें, शासन को नवीन भवन के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज चुके है। माारारपारा में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र संज्ञान में आया है।

श्री माणिकेश्वर महादेव मंदिर बना आदिवासी विवाह का नया आस्था केन्द्र

कोंटा। नगर में स्थित 400 वर्ष पूर्व प्राचीन प्रसिद्ध शिवधाम श्री श्री श्री माणिकेश्वर महादेव मंदिर, कोंटा आदिवासी समाज की गहरी आस्था का प्रमुख केन्द्र बनता जा रहा है। वर्षों से धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रहे इस मंदिर परिसर में एक ऐतिहासिक वैवाहिक आयोजन संपन्न हुआ, जिसने स्थानीय समाज का ध्यान आकर्षित किया। परंपरागत रूप से आदिवासी समाज में विवाह समारोह अपने-अपने ग्राम-गृहों में सम्पन्न करने की परंपरा रही है। किंतु इस परंपरा से अलग हटकर ग्राम आसिरगुड़ा निवासी चिरंजीवी बी. लक्ष्मैया ने अपनी जीवन संगिनी के रूप में सीमावर्ती राज्य उड़ीसा के ग्राम मल्लावरम की वधू सौ. रश्मिता के साथ माणिकेश्वर स्वामी के पावन सानिध्य में सात फेरे लिए। विवाह समारोह वैदिक मंत्रोच्चार, पारंपरिक रीति-रिवाज और धार्मिक विधि-विधान के साथ सम्पन्न हुआ। मंदिर प्रांगण में गूंजते मंत्रों और हर-हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। बड़ी संख्या में ग्रामीण, श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक इस शुभ अवसर के साक्षी बने। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पी. विजय नायडू तथा पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष बोड्डू राजा जी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। उपस्थित जनों ने नवदम्पति को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय दांपत्य जीवन की कामना की। उल्लेखनीय है कि श्री माणिकेश्वर महादेव मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थल ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का भी केन्द्र बनता जा रहा है। इस प्रकार का आयोजन यह दर्शाता है कि आदिवासी समाज अपनी परंपराओं के साथ-साथ धार्मिक आस्था के नए आयामों को भी आत्मसात कर रहा है। यह विवाह समारोह न केवल दो परिवारों के मिलन का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक सौहार्द, सांस्कृतिक आदान- प्रदान और क्षेत्रीय एकता का भी प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर गया।

अधीक्षण अभियंता ने किया पर्रेबानगांव सीसी रोड का निरीक्षण, गुणवत्ता सुधार के दिए निर्देश

फरसगांव/केशकाल। मुख्यमंत्री गौरवपथ योजना के तहत ग्राम पर्रेबानगांव, विकासखंड फरसगांव में निर्माणाधीन सीसी रोड का 25 फरवरी 2026 को अधीक्षण अभियंता डी.पी. भूआर्य ने औचक निरीक्षण किया। करीब 41.73 लाख रुपये की लागत से आंगनबाड़ी से मंसू घर तक 500 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य जारी है। निरीक्षण के दौरान कांकेर मंडल से पहुंचे अधीक्षण अभियंता डी.पी. भूआर्य ने निर्माण स्थल का बारीकी से जायजा लिया और गुणवत्ता व प्रगति की समीक्षा की। साथ ही निर्माण कार्य को ग्राम गौरवपथ योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता भुआर्य ने निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता को लेकर असंतोष जताते हुए उन्होंने सहायक अभियंता, उप अभियंता और ठेकेदार पर नाराजगी व्यक्त की। स्पष्ट कहा गया कि शासन की योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्राम गौरवपथ योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं होने पर कार्यपालन अभियंता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता बलराम सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्य को निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण कराने तथा भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया। साथ ही लापरवाही पाए जाने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और संबंधित सब इंजीनियर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री गौरवपथ योजना के अंतर्गत बनने वाली यह सड़क क्षेत्र के ग्रामीणों के आवागमन को सुगम बनाएगी और स्थानीय विकास को गति प्रदान करेगी।

तेंदू पत्ता बूटा कटाई के संबंध में दी गई तकनीकी जानकारी, 1 लाख मानक बोरा से अधिक संग्रहण का लक्ष्य

जिला यूनियन में शाखकर्तन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन

भानुप्रतापपुर। जिला यूनियन पूर्व के द्वारा एकदिवसीय तेंदूपत्ता शाख़कर्तन सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमे तेंदू पत्ता के बूटा कटाई को लेकर तैयारी के सम्बंध में दुर्गुकोंदल एवं भानुप्रतापपुर परिक्षेत्र के पोषक अधिकारी, प्रबंधक व फड़ मुंशियों सहित संग्राहक परिवार के सदस्यों एवं वन कर्मचारियों को जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए उप प्रबन्ध संचालक दीपक गावड़े ने कहा कि 15 मार्च तक बूटा कटाई का कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण करें ऐसा करने वाले पोषक अधिकारी, प्रबंधक व फड़ मुंशियों को अच्छा कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह वनमंडल तेंदूपत्ता कार्य मे पूरे प्रदेश में अव्वल हैं। हर बार 1 लाख मानक बोरा का लक्ष्य पूरा किया जाता है, इस बार भी ज्यादा से ज़्यादा कलेक्शन पर ध्यान देना है। टीकम टांडिया पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जिला यूनियन ने कहा कि जिस प्रकार एक किसान खेती के पूर्व तैयारियां करता है उसी प्रकार पत्ता तोड़ाई के पूर्व भी बूटा कटाई के रुप में तैयारी करनी पड़ती है। इसे रोजी के रूप में नहीं बल्कि आंदोलन के रुप में करें। पत्ते की गुणवत्ता अच्छी होने पर बोनस भी अच्छा मिलता है। पत्ता तोड़ाई कार्य मे समय काफी महत्वपूर्ण होता है बूटा कटाई से लेकर उसे गोदामों तक पहुचाने का कार्य सुरक्षित रूप से समय पर करना हैं। वनों को आग से बचाने हेतु गांव में बैठक कर सबको समझाइश दी जाए ताकि वनों में छोटे छोटे पौधों सहित वन्य जीवों को नुकसान न पहुँचे। वन क्षेत्र पाल बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि वनोजप से सम्बंधित तकनीकी जानकारी हेतु यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, इसका पालन अवश्य करें। हम सब प्रकृति की गोद मे रहते हैं यहाँ को अधिकांश लोग वनोपज से अपनी जीविका चलते हैं। शासन का भी उददेश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक वनोपज से मिलने वाले लाभ को पहुँचाया जाए। तेंदू पत्ता तोड़ाई एक महाउत्सव है इसे अच्छे से मनायें। सोना कई प्रकार का होता है और ये हरा सोना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच रही है कि ग्रामीणों तथा संग्राहकों का आर्थिक उन्नयन किया जाए उसी दिशा में सहकारिताकरण किया गया है। जितना अच्छा धूप पौधे को मिलेगा उतना ही अच्छा पत्ता निकलेगा। उन्होंने फड़ मुंशियों से अपील की है कि बूटा कटाई अच्छे से करवाने ग्रामीणों को सही से समझाइश दें। अंतागढ़ जनपद के पूर्व अध्यक्ष बद्री गावड़े ने हरा सोना इसे कभी न खोना की तर्ज पर तेंदू पत्ता को कृषि उपज के समकक्ष बताया। उन्होंने कहा कि मैं स्वंय संग्राहक परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हु और पत्ता तोड़ाई करता हू। रेंजर साहब ने जो तकनीकी जानकारी दी है उसका सभी ईमानदारी से पालन करें। बूटा कटाई अच्छे से करें क्योंकि ऊपर से कटाई करने पर कमजोर पौधा निकलेगा जिससे पत्ते भी सही नहीं मिलेंगे। गर्मी का समय बूटा कटाई के लिए उपयुक्त है पत्ते अच्छे होंगे तो इसका लाभ भी अधिक मिलेगा। इस दौरान आई पी गेन्द्रे उप वनमंडलाधिकारी, वासुदेव आंधिया अध्यक्ष जिला यूनियन पूर्व भानुप्रतापपुर, सतेंद्र बघेल संचालक सदस्य, देवराज नाग, निर्मला ध्रुव, रानुराम मंडावी, जगतराम दुग्गा, सिया राम पोटाई, सतीश मिश्रा वन परिक्षेत्र अधिकारी दुर्गुकोदल, अखंड प्रताप तिवारी, एकता कर वन क्षेत्रपाल।

दन्तेवाड़ा एवं कुआकोंडा ब्लॉक में चल रहे निर्माण कार्यों का किया कलेक्टर ने पुन: निरीक्षण

दंतेवाड़ा। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव द्वारा दंतेवाड़ा विकासखंड के ग्राम गामावाड़ा से मसेनार (3 किमी) एवं धुरली मरकानार (3.75 किमी) तक निर्माणाधीन सीसी सड़क का पूनः निरीक्षण करते हुए कार्य प्रगति की जानकारी ली। और कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस क्रम में उन्होंने मरकानार मुंडीपारा में वीसीडब्ल्यू पुलिया निर्माण के प्रस्ताव पर अधिकारियों से चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि एसएच-5 से 3 किलोमीटर दूर मोलसनार ग्राम पंचायत से बहने वाली लाल नदी में पुल निर्माण की मांग स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की जाती रही है। साथ ही पुल न होने से वर्षा के दिनों में मरकानार और मुंडीपारा के ग्रामीणों को भारी असुविधा होती थी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यहां पुल निर्माण की पहल की गई है। इस क्रम में आज कलेक्टर ने खालेपारा में डीपीआर के अंतर्गत प्रस्तावित पुल निर्माण को लेकर एसडीओ के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को शीघ्र अनुमानित लागत प्रस्ताव (प्राक्कलन) तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा, जिससे बचे कार्य जल्द प्रारंभ किए जा सकें। इसके अलावा उन्होंने सभी कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने और गुणवत्ता बनाए रखने को भी कहा। इसके पश्चात कलेक्टर ने किरंदुल में निर्माणाधीन आस्था-2 विद्या मंदिर के स्थल का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों और कार्य एजेंसियों से वर्तमान स्थिति की जानकारी ली तथा अब तक हुए कार्यों का जायजा लिया।

कोंटा में आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर अहम बैठक

कोंटा। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र कोंटा में संचालित आश्रम, पोटाकेबिन एवं अन्य आवासीय विद्यालयों की शैक्षणिक और व्यवस्थागत गुणवत्ता की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि विद्यार्थियों की पढ़ाई, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनपद अध्यक्ष कुसुमलता कवासी एवं जनपद उपाध्यक्ष व कोंटा ब्लॉक शिक्षा समिति के अध्यक्ष माड़वी हिड़मा की पहल पर कोंटा आईटीआई कॉलेज के सभाकक्ष में बैठक आयोजित हुई। इसमें श्रीनिवास राव (बीईओ कोंटा), मंडल संयोजक पी श्रीनिवास सहित आश्रम व पोटाकेबिन विद्यालयों के अधीक्षक, सीआरसी समन्वयक और शिक्षक उपस्थित रहे। बैठक में विद्यार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, भोजन व्यवस्था, अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अधीक्षकों को नियमित मॉनिटरिंग और समयबद्ध पाठ्यक्रम पूर्ण करने के निर्देश दिए। जनपद अध्यक्ष कुसुमलता कवासी ने कहा कि आश्रम व पोटाकेबिन विद्यालय आदिवासी बच्चों के भविष्य की आधारशिला हैं, इसलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं माड़वी हिड़मा ने कहा कि कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाएं और हर माह प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बैठक में प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया, ताकि शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जाए।

रायपुर में आयोजित शिविर में नारायणपुर के तीन दिव्यांगजनों को नि:शुल्क बायोनिक हाथ प्रदाय

नारायणपुर। अस्थिबाधित दिव्यांगजन जिनके हाथ कोहनी से नीचे कटे हुए हैं, उनके पुनर्वास एवं सशक्तिकरण हेतु Inali Foundation द्वारा समाज कल्याण विभाग के समन्वय से 20 से 23 फरवरी तक रायपुर में निःशुल्क कृत्रिम बायोनिक हाथ वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाज कल्याण विभाग, जिला नारायणपुर द्वारा जिले से तीन चिन्हांकित अस्थिबाधित दिव्यांगजनों को शिविर में उपस्थित कराया गया। इनमें ग्राम बावड़ी निवासी जमदेर पोटाई, ग्राम गरांजी के निवासी सुनिल कुमार तथा नयापारा के निवासी जयचंद शामिल थे। तीनों लाभार्थियों के हाथ कोहनी से कलाई के बीच कटे हुए थे। शिविर के दौरान विशेषज्ञ टीम द्वारा परीक्षण एवं माप लेने के उपरांत इन दिव्यांगजनों को निःशुल्क बायोनिक हाथ प्रदान किए गए। कृत्रिम हाथ प्राप्त कर लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा शासन-प्रशासन एवं संस्था के प्रति आभार प्रकट किया। समाज कल्याण विभाग ने बताया कि इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

पीएम स्कूल केशकाल के विद्यार्थियों ने कृषि विज्ञान केंद्र, केरलापाल का किया शैक्षणिक भ्रमण

नारायणपुर। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय केशकाल के 75 छात्र-छात्राओं ने कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान कृषि विशेषज्ञ डॉ. हरेंद्र, डॉ. आलिया अफरोज एवं डॉ. अंकिता सिंह ने विद्यार्थियों को केंद्र में स्थापित विभिन्न इकाइयों का अवलोकन कराया। विशेषज्ञों ने बच्चों को विशेष रूप से हर्बल गुलाल बनाने की विधि, वर्मी कम्पोस्ट, मशरूम उत्पादन और उन्नत नर्सरी प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी। फूलों और प्राकृतिक संसाधनों से तैयार होने वाले हर्बल गुलाल की इकाई बच्चों के आकर्षण का केंद्र रही। इस एक्सपोजर विजिट का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक कृषि तकनीकों और ग्रामीण स्वरोजगार के वैज्ञानिक तरीकों से व्यावहारिक रूप से अवगत कराना था जिसमें छात्रों का काफी रुचि देखा गया।

संयुक्त सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दुर्घटना संभावित स्थलों का किया गया निरीक्षण

दंतेवाड़ा। जिला परिवहन कार्यालय से दी गई जानकारी अनुसार संयुक्त सड़क सुरक्षा समिति द्वारा नगरीय क्षेत्र अंतर्गत दुर्घटना संभावित स्थलों का निरीक्षण कर सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ), यातायात पुलिस, नगरपालिका तथा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारी उपस्थित रहे। प्राप्त सूत्रों के अनुसार कलेक्टर के निर्देश पर नगरीय क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस क्रम में दुर्घटना संभावित स्थलों पर स्पीड ब्रेकर एवं रंबल स्ट्रिप्स के अलावा सावधानी सूचक बोर्ड, जेब्रा क्रॉसिंग, सड़क चिह्नांकन एवं यातायात संकेतक स्थापित किए जाएंगे तथा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाने, आवश्यकता अनुसार विद्युत पोल स्थानांतरित करने तथा यात्री प्रतीक्षालयों में यात्रियों की सुविधा हेतु रैंप एवं सीढ़ियों के निर्माण के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त खुली नालियों एवं मैनहोल को ढकने तथा खराब स्ट्रीट लाइटों को शीघ्र दुरुस्त करने हेतु संबंधित विभागों त्वरित कार्यवाही करने को कहा गया।

रमजान विवाद में उलझी सियासत, अमीन मेमन ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष से मांगा स्पष्टीकरण

केशकाल। छत्तीसगढ़ में रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटे पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दिए जाने संबंधी कथित आदेश पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। सोशल मीडिया पर 19 तारीख को जारी एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें शासन की ओर से ऐसी अनुमति दिए जाने की बात कही गई थी। हालांकि बाद में उक्त पत्र को हटा लिया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन ने इस मामले में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रेसवार्ता के माध्यम से अमीन मेमन ने कहा कि वायरल पत्र में रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यालय से एक घंटा पहले जाने की अनुमति का उल्लेख था, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। इसके अगले ही दिन अल्पसंख्यक विभाग के सचिव अनुपम द्विवेदी ने आधिकारिक पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि राज्य शासन की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और सोशल मीडिया में प्रसारित जानकारी पूरी तरह भ्रामक एवं आधारहीन है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर सच कौन बोल रहा है- वक्फ बोर्ड अध्यक्ष या शासन का आधिकारिक विभाग। उन्होंने मांग की कि यदि गलत जानकारी प्रसारित की गई है तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेमन ने वक्फ बिल को लेकर दिए गए बयानों पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना है कि यदि नया वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है, तो पुराने और नए कानून के अंतर और उससे मिलने वाले लाभ स्पष्ट किए जाएं। साथ ही जुमे की नमाज में तकरीरों के विषय तय करने संबंधी किसी भी निर्देश को उन्होंने धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप बताया। उन्होंने कहा कि भ्रामक जानकारी से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और संबंधित व्यक्ति को इस मामले में सार्वजनिक स्पष्टीकरण देना चाहिए तथा गलती होने पर माफी मांगनी चाहिए।

संक्षिप्त समाचार

सांतरागाछी-रानी कमलापति-सांतरागाछी हमसफ़र एक्सप्रेस का अनूपपुर में, उत्कल एक्सप्रेस का वेंकटनगर तथा निजामुद्दीन-अम्बिकापुर- निजामुद्दीन एक्सप्रेस का कोतमा स्टेशन में ठहराव का लोकार्पण माननीया सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह द्वारा किया गया

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा लगातार यात्री सुविधाओं का क्रमिक विकास एवं उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है । इसी कड़ी में अनूपपुर स्टेशन में गाड़ी संख्या 22170 सांतरागाछी-रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस का दिनांक 27 फरवरी 2026 से एवं गाड़ी संख्या 22169 रानी कमलापति-सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस का दिनांक 05 मार्च 2026 से, कोतमा स्टेशन में गाड़ी संख्या 22408 निजामुद्दीनङ्कअम्बिकापुर एक्सप्रेस का 04 मार्च 2026 से एवं गाड़ी संख्या 22407 अम्बिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस का 05 मार्च 2026 से तथा वेंकटनगर स्टेशन में गाड़ी संख्या 18477 पुरी-योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस का दिनांक 27 फरवरी 2026 से एवं गाड़ी संख्या 18478 योगनगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस का दिनांक 28 फरवरी 2026 से उपलब्ध कराई गई है इस सुविधा का लोकार्पण आज श्रीमती हिमाद्री सिंह माननीया सांसद, शहडोल के कर कमलों द्वारा किया गया इस अवसर पर अनूपपुर स्टेशन में आयोजित लोकार्पण समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री के श्रीनिवास, मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री एस भारतीयन सहित अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा भारी संख्या में नागरिक उपस्थित थे । कार्यक्रम के प्रारंभ में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री के श्रीनिवास द्वारा माननीया सांसद एवं सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुये माननीया सांसद, श्रीमती हिमाद्री सिंह ने कहा कि यह गरिमामय समारोह इस क्षेत्रवासियों के लिए सुखद पल है इन गाड़ियों के ठहराव की सुविधा के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई दी तथा माननीय प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया उन्होने रेलवे द्वारा किया जा रहे अधोसंरचना विकास, यात्री सुविधा विकास, सुरक्षा तथा संरक्षा विकास कार्य के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की

जल संचय जल संरक्षण मोर गाँव मोर पानी : सचिव, देवदास मानिकपुरी, भरारी पंचायत

बिलासपुर। जिला बिलासपुर के जनपद पंचायत तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत भरारी में कार्यक्रम रखा गया जिसमें महाराष्ट्र से आये श्रद्धा सबुरी समाज सेवी संस्था, जिला पांडूरना, मध्यप्रदेश राज्य द्वारा गाँव गाँव में जल संरक्षण के संबंध में जागरूकता व वाटर हाइवे स्ट्रिंग पानी की उपयोगिता जल संचयन पोस्टर बैनर रैली एवं प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्राम वासियों को बताये गए जलमेन, मास्टर मेन वी. वानखेड़े एवं उनके सहयोगी द्वारा बहुत ही अच्छे से ग्राम वासियों को जल संचयन जल संरक्षण की बार में विस्तृत रूप से बताया गया व आने वाले 50 वर्षो तक हम कैसे पानी बचाकर अपने आने वाले भविष्य को जल की उपलब्धता बनाये रख सकते हैं इस कार्यक्रम ग्राम पंचायत भरारी, नेवरा, कपसिया कला, टांडा, कपसिया खुर्द शामिल हैं, अध्यक्ष श्रद्धा सबुरी समाज सेवी संस्था पांडूरना मध्यप्रदेस, सरपंच भरारी सुश्री सुमिता टंडन, अमिता कौशिक, गणेश खांडे, संजय कौशिक, अजय कौशिक, अश्वनी भास्कर, पंचगण देवकान्त भास्कर, घनश्याम साहू द्वारिका दुबे, दुर्गेश निर्मलकर, राकेश साहू, त्रिजोगी साहू, पद्मनी उजागर, अश्वनी वस्त्रकार, अनीता उजागर रोजगार सहायक, सचिव ग्राम भरारी देवदास मानिकपुरी, उमेश पटेल, ग्रामवासी केदार साहू, पुनाराम, भनेश, रामचरण यादव, देवचरण, मुनीम श्रीवास, लक्ष्मण दास, रजनीकांत, सुनील अनीता, राजकुमारी एवं स्वच्छकांछी एवं आवास के ग्राम पंचायत भरारी, नेवरा, कपसिया कला, टांडा, कपसिया खुर्द शामिल हैं

होली त्यौहार से पहले किसानों की दीवाली

24.28 लाख किसानों के खाते में 10324 करोड़ राशि का करेंगे अंतरण

■ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 263 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण-शिलान्यास

बिलासपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 28 फरवरी को अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान जिले में 263 करोड़ 16 लाख 81 हजार रुपये की लागत के 89 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन करेंगे। जिसमें 15 करोड़ 98 लाख 53 हजार रुपये की लागत के 7 कार्यों का लोकार्पण एवं 247 करोड़ 18 लाख 28 हजार रुपये की लागत के 82 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। वे बिल्हा विकासखण्ड के रहंगी खेल मैदान में दोपहर 12 बजे कृषक उन्नति योजना अंतर्गत 24.28 लाख किसानों के खाते में 10324.84 करोड़ रूपए आदान सहायता राशि का अंतरण करेंगे एवं वृहद किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। इनमें बिलासपुर जिले के 1 लाख 25 हजार 352 किसान शामिल है जिनके खाते में 494.38 करोड़ रूपए की राशि अंतरित होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू करेंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव एवं श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक सर्वश्री श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल, श्री धरमजीत सिंह, श्री सुशांत शुक्ला, श्री दिलीप लहरिया, श्री अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी, छत्तीसगढ़ राज्य पाठय पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पाण्डेय एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 3 करोड़ 51 लाख 15 हजार की लागत के रतनपुर कोटा लोरमी मार्ग में स्थित चांपा नाला पर सेतु निर्माण कार्य, 2 करोड़ 50 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर निर्माण कार्य, 75 लाख की लागत से मस्तुरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन लुथरा निर्माण कार्य, 2 करोड़ 20 लाख 65 हजार की लागत से खारंग जलाशय के स्पील चैनल के शूटफॉल, बांयी तट पर प्रोटेक्शन वॉल तथा स्पील चैनल के बेड में कांक्रीटिंग कार्य, 2 करोड़ 6 लाख 79 हजार की लागत से बिल्हा ब्लॉक में लोकल नाला पर देवकिरारी स्टापडेम निर्माण कार्य, 2 करोड़ 86 लाख 9 हजार की लागत से बिल्हा ब्लॉक में बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के मोहतरा वितरक नहर लाईनिंग, चैनल निर्माण एवं मरम्मत कार्य एवं 2 करोड़ 8 लाख 85 हजार की लागत से लोकल नाला पर परसदा (उमरिया) स्टापडेम निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1 अंतर्गत 20 करोड़ 41 लाख की लागत से सीपत बलौदा कोरबा मार्ग लंबाई 14.40 किमी में मजबूतीकरण कार्य, 8 करोड़ 39 लाख 98 हजार की लागत से हथनी नवागांव गोड़ी उड़गन मार्ग लंबाई 5.75 किमी निर्माण कार्य, 10 करोड़ 3 लाख 90 हजार की लागत से मोपका खैरा गतौरा जयरामनगर मार्ग कुल लंबाई 13.66 किमी (मुख्य जिला मार्ग क्र-07) किमी 1, 2 एवं 7 से 14/8 तक 9.70 किमी में मजबूतीकरण निर्माण कार्य, 7 करोड़ 41 लाख 67 हजार की लागत से नेवसा से गढ़वट मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 6.325 किमी, 1 करोड़ 64 लाख 46 हजार की लागत से सेलर बरभांठा मार्ग लंबाई 1. 20 किमी का निर्माण कार्य, 1 करोड़ 63 लाख की लागत से एफसी.आई. गोदाम से राजकिशोर मार्ग लंबाई 0.55 किमी का निर्माण कार्य, 19 करोड़ 5 लाख 17 हजार की लागत से सोनसरी से मुकुंदपुर पहुंच मार्ग लंबाई 8.675 किमी का निर्माण कार्य, 3 करोड़ 48 लाख 34 हजार की लागत से लिंक रोड मार्ग लंबाई 2.50 किमी. का उन्नयन कार्य, 1 करोड़ 2 लाख 65 हजार की लागत से लिम्हा से बरपाली मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 1 किमी, 2 करोड़ 73 लाख 94 हजार की लागत से अमतरा लछनपुर मार्ग लंबाई 2 किमी का निर्माण कार्य, 1 करोड़ 84 लाख 65 हजार की लागत से देवकीनंदन चौक से महामाया चौक मार्ग लंबाई 1.30 किमी निर्माण कार्य, 8 करोड़ 30 लाख 71 हजार की लागत से कोनी।

माह फरवरी में सेवानिवृत्त हो रहे मंडल रेल परिवार के 01अधिकारी सहित 21 सदस्यों को दी गई भावभीनी विदाई

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के विभिन्न विभागों में कार्यरत् सहायक परिचालन प्रबंधक सहित 21 रेल परिवार के सदस्य माह फरवरी 2026 में अपनी गौरवशाली रेल सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मंडल कार्मिक सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त हो रहे समस्त कर्मचारियों को ससम्मान विदाई दी गई । इस अवसर पर सहायक कार्मिक अधिकारी श्री रंजन कुमार रुखैयार द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को बंदोबस्त भुगतान से संबंधित समस्त दस्तावेज,सेवा प्रशस्ति प्रमाण-पत्र एवं सेवा मैडल आदि प्रदान किया गया 7 इस दौरान मुख्य कार्यालय अधीक्षक (आईटी) श्री सेवक रजक द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उम्मीद कार्ड (मेडिकल) व बंदोबस्त से संबन्धित नियमों से अवगत कराया गया 7 समारोह में सेवानिवृत्त कर्मियों के परिजन, मंडल कल्याण निरीक्षक एवं कार्मिक निपटारा शाखा के कर्मचारी भी उपस्थित रहे । मंडल के सेवानिवृत्त हो रहे 21 रेल परिवार के सदस्यों में परिचालन विभाग से 02, इंजीनियरिंग विभाग से 09, विद्युत विभाग से 07, यांत्रिक विभाग से 02, तथा वाणिज्य विभाग से 01 कर्मचारी शामिल हैं । इस अवसर पर सहायक कार्मिक अधिकारी ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी गौरवशाली रेल सेवा के लिए बधाई दी तथा तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कामना की गई

अंकित गौरहा:जमीन के सवाल,लेकिन जनता बेहाल-बेलतरा में उठे नए प्रश्न

बिलासपुर। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति इन दिनों फिर चर्चा में है। क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला विधानसभा सत्र में अपने सवालों को लेकर सुर्खियों में हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या उनके मुद्दे वास्तव में क्षेत्र की प्राथमिक समस्याओं को दर्शाते हैं, या केवल जमीन, टावर और अतिक्रमण जैसे विषयों तक सीमित हैं? पूर्व जिला पंचायत सभापति और कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने तंज कसते हुए कहा कि विधायक महोदय जमीन से जुड़े तो जरूर हैं, लेकिन उनके सवाल भी सिर्फ जमीन और टावरों के इर्द-गिर्द ही घूमते नजर आते हैं। कभी बिलासपुर को उड़ता पंजाब बताने की बात हो, तो कभी चौड़ीकरण के नाम पर लिंगियाडीह खाली करवाने का संकल्प—इन बयानों ने क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। अंकित गौरहा का आरोप है कि विधानसभा सत्र के दौरान शासकीय जमीनों को खाली कराने, बिल्डरों की जांच और टावरों से जुड़े प्रश्नों पर तो जोर दिखता है, लेकिन बेलतरा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत समस्याएं—सड़क, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा—पर अपेक्षित आवाज नहीं उठ रही। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में हाल के दिनों में बढ़ती आपराधिक और राजनीतिक घटनाओं ने सरकार की छवि पर भी असर डाला है। ऐसे में जनता यह जानना चाहती है कि उनके प्रतिनिधि क्षेत्र के व्यापक विकास और जनहित के मुद्दों को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। अब निगाहें आगामी विधानसभा सत्र पर टिकी हैं—क्या बेलतरा की आवाज सदन में व्यापक रूप से गूंजेगी, या बहस जमीन और टावरों तक ही सीमित रहेगी..?

आध्यात्मिक उत्थान मंडल ट्रस्ट के वार्षिक नि:शुल्क चिकित्सा शिविर हेतु पोसैता स्टेशन में 02 एक्सप्रेस गाड़ियों का अस्थायी ठहराव की सुविधा

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा आध्यात्मिक उत्थान मंडल ट्रस्ट के वार्षिक नि:शुल्क चिकित्सा शिविर में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिनाँक 28 फरवरी से 06 मार्च 2026 तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने/गुजरने वाली 02 एक्सप्रेस गाड़ियों का अस्थायी ठहराव दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के पोसैता स्टेशन में 01 मिनट के लिए दिया जा रहा है। विवरण इस प्रकार है :- दिनाँक 28 फरवरी से 06 मार्च 2026 तक दुर्ग से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस पोसैता स्टेशन में ठहराव के साथ चलेगी 7 यह गाड़ी पोसैता स्टेशन 16.09 बजे पहुंचेगी तथा 16.10 बजे रवाना होगी दिनाँक 28 फरवरी से 06 मार्च 2026 तक आरा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस पोसैता स्टेशन में ठहराव के साथ चलेगी यह गाड़ी पोसैता स्टेशन 09.58 बजे पहुंचेगी तथा 09.59 बजे रवाना होगी दिनाँक 28 फरवरी से 06 मार्च 2026 तक पुरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18477 पुरी-योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस पोसैता स्टेशन में ठहराव के साथ चलेगी 7 यह गाड़ी पोसैता स्टेशन 07.34 बजे पहुंचेगी तथा 07.35 बजे रवाना होगी दिनाँक 28 फरवरी से 06 मार्च 2026 तक योगनगरी ऋषिकेश से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18478 योगनगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस पोसैता स्टेशन में ठहराव के साथ चलेगी यह गाड़ी पोसैता स्टेशन 15.38 बजे पहुंचेगी तथा 15.39 बजे रवाना होगी

दिव्यांगजनों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचे: अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया

■ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष ने शहर के दिव्यांग संस्थाओं, विशेष विद्यालयों एवं छात्रावासों का किया निरीक्षण

■ योजनाओं की समीक्षा कर बेहतर क्रियान्वयन के दिए निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया ने आज कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एसएसपी श्री रजनेश सिंह एवं संबंधित अधिकारियों के से चर्चा कर जिले में दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति, लाभार्थियों की स्थिति तथा भविष्य की कार्ययोजना पर भी विचार विमर्श किया। श्री कावड़िया ने दिव्यांगजनों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने दिव्यांगजनों के ऋण प्रकरणों, यूडीआईडी कार्ड निर्माण, सहायक उपकरण वितरण और शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में निरंतर शिविरों के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों को योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही स्वरोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास भी जारी हैं। अध्यक्ष श्री कावड़िया ने निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अधिकतम पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार से जोड़ते हुए दिव्यांगजनों के लिए स्थायी आय के अवसर विकसित किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि जरूरतमंद हितग्राहियों को शीघ्र सहायता मिल सके। अध्यक्ष श्री कावड़िया ने शहर में संचालित दिव्यांग संस्थाओं, विशेष विद्यालयों एवं छात्रावासों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां अध्ययनरत बच्चों और प्रशिक्षुओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

कलेक्टर-एसएसपी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक,पर्व में अनहोनी से निपटने जिला प्रशासन का पुख्ता इंतजाम

■ होली एवं ईद पर्व आपसी भाईचारे एवं सामाजिक सौहार्द के साथ मनाने का निर्णय

बिलासपुर। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आज यहां जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं एसएसपी श्री रजनेश सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में होलिका दहन, 4 मार्च को होली एवं आगामी ईद-उल-फित्र पर्व को आपसी तालमेल एवं भाईचारे की भावना के साथ सौहार्द्रपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि जिले में सभी धर्मों एवं सम्प्रदाय का सम्मान करते हुए भाईचारे के साथ सभी धर्मों के पर्वों और उत्सवों को मनाने की वैभवशाली परम्परा रही है। उन्होंने कहा कि यह परम्परा आगे भी जारी रखनी है। एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने कहा कि यह सामाजिक सौहार्द का पर्व है। सुरक्षा के सारे मापदण्डों का पालन किया जाएगा। असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, हुड़दंगियों पर, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानों पर मुखौटे बेचना प्रतिबंधित होगा। बैठक में पर्व के दौरान आपात सहायता एवं किसी भी तरह की अनहोनी को टालने के लिए पुलिस सहित नगर पालिक निगम, नगर सेना एवं सिम्स एवं जिला अस्पताल, विद्युत मण्डल आदि विभागों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। समिति के सदस्यों ने पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने पर अपनी-अपनी सहमति जताई। नगर पालिक निगम द्वारा होलिका दहन स्थलों को चिन्हांकित कर साफ-सफाई कराई जाएगी। नियमित रूप से दो तीन बार पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था भी निगम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस विभाग को पर्व के दौरान शहर के समस्त चौक-चौराहों, धार्मिक स्थलों, सिम्स, जिला अस्पताल सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए गए है। बीच सड़क पर डिस्क एवं बिजली तार के नीचे होलिका दहन नहीं किया जाएगा। पेट्रोलिंग पार्टी की संख्या बढ़ाकर मुख्य मार्गों के साथ-साथ अंदर की गलियों में गश्त की जाएगी। नगर सेना द्वारा फायर बिग्रेड वाहन मुस्तैद रखा जाएगा। सिम्स एवं जिला अस्पताल इस दौरान 24 घंटे खुले रहेंगे। विद्युत विभाग को पर्व के दौरान विद्युत की निरंतर आपूर्ति बनाये रखने एवं आपात स्थिति में सुधार के लिए कर्मचारियों की टीम तैनात रखे जाने के निर्देश दिए गए है। बैठक में एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहरी श्री पंकज पटेल, एसडीएम श्री मनीष साहू, शांति समिति के सदस्य श्री हबीब मेमन, श्री सुधीर खण्डेलवाल, श्री चंचल सलूजा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अजीत मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद थे।

होली पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्ग-रायगढ़-दुर्ग के मध्य 04फेरे के लिए होली मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में होली पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दिनांक 02, 03, 05 एवं 06 मार्च 2026 को गाड़ी संख्या 08834/08833 दुर्ग - रायगढ़ - दुर्ग के मध्य 04 फेरे के लिए होली मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही हैं । गाड़ी संख्या 08834 दुर्ग रायगढ़ मेमू पैसेंजर गाड़ी दुर्ग से 10:30 बजे रवाना होकर 10:36 बजे भिलाई नगर 10.43 बजे भिलाई पावर हाउस 10:50 बजे भिलाई 10.56 बजे देवबलोदा चरोदा, 11:09बजे कुम्हारी, 11:17 बजे सरोना 11.24 बजे सरस्वती नगर, 11.35 बजे रायपुर 11:45 बजे डब्ल्यूआरएस, 11:52 बजे उरकुरा, 12:00 मांडर,12:11 बजे सिलियारी, 12.21 बजे बैकुंठ 12:28 बजे तिल्दा नेवरा, 12.39 बजे हथबंद, 12:52 बजे भाटापारा, 13.05 बजे निपानिया, 13.15 बजे दागोरी, 13.23 बजे बिल्हा, 14.31 बजे चक्करभाटा 14.37 बजे दाधापारा,15.10 बजे बिलासपुर, 15.28 बजे गतौरा, 15:40 बजे जयरामनगर, 15.53 बजे अकलतरा, 16:10 बजे जांजगीर नैला, 16:30 बजे चांपा, 16:50 सारागांव देवरी, 17:03 बजे बुढार, 17.18 बजे सक्ती, 17:30 जारडीह, 17.40 बजे खरसिया, 17.58 बजे रॉबर्टसन, 18: 13 बजे भूपदेवपुर, 18.23 बजे किरोड़ीमल नगर, 18:50 बजे रायगढ़।

हेल्दी और फिट रहना है तो पिएं टमाटर सूप

लाल लाल स्वादिष्ट टमाटर कई सब्जियों व डिश का अहम हिस्सा होते है। कच्चे टमाटर के अलावा उनका सूप भी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। आमतौर पर खाने से पहले स्टार्टर के तौर पर लिए जाने वाले टमाटर सूप में विटामिन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो आपको हेल्दी और फिट रखने में मदद करते हैं। आइए, जानते हैं टमाटर सूप पीने से सेहत को मिलने वाले गजब के फायदे

हड्डियों के लिए फायदेमंद

टमाटर सूप में विटामिन के और केल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत रखता है। इसके अलावा शरीर में लाइकोपीन की कमी होने से भी हड्डियों पर तनाव बढ़ता है और टमाटर में काफी मात्रा में लाइकोपीन होता है, जो हड्डियों के लिए अच्छा होता है।

दिमाग को रखें दुरुस्त

टमाटर सूप में भरपूर मात्रा में कॉपर और पोटेशियम पाया जाता है, जिससे नर्वस सिस्टम ठीक रहता है और दिमाग को मजबूती मिलती है।

विटामिन की कमी करे पूरी

टमाटर सूप में विटामिन इ और ए अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन इ, टिशू के विकास के लिए जरूरी होता है। कहते है कि शरीर में रोजाना 16% विटामिन इ और 20% विटामिन ए की जरूरत होती है और टमाटर सूप इसकी जरूरत को पूरा करता है।

वजन करे कम

टमाटर सूप को अगर ऑलिव ऑयल से बनाया जाए तो यह वजन घटाने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे आपको काफी समय तक भूख नहीं लगती।

कैंसर का खतरा करे कम

टमाटर सूप में लाइकोपीन और कैरोटोनॉयड जैसे एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे कैंसर की आशंका कम हो जाती है।

ब्लड शुगर को करे नियंत्रण

डायबिटीज के मरीजों को डाइट में टमाटर सूप जरूर लेना चाहिए। इसमें क्रोमियम होता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने में सहायक होता है।

रक्त प्रवाह को बढ़ाएं

टमाटर में सेलेनियम होता है, जो रक्त प्रवाह को बढ़ाता है जिससे एनिमिया का खतरा कम हो जाता है।

शरीर को ब्रेकफास्ट वाली एनर्जी देती है किशमिश

बहुत से लोगों को सुबह उठने के बाद सुस्ती महसूस होती है, ऐसे में जागते तो हैं लेकिन थोड़ी ही देर बाद नींद आने लगती है। अगर आप सुबह पूरी एनर्जी के साथ उठना चाहते हैं तो किशमिश आपके रूटीन को बेहतर बना सकती है।

सुबह-सुबह उठना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपके रूटीन में सुबह जल्दी उठने की आदत है तो समझिए आपके सारे काम सही तरीके से बनते हैं। साथ ही आप तमाम तरह की सेहत संबंधी समस्याओं से भी दूर रहेंगे। हालांकि, मौजूदा दौर में इस आदत को बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं। वजह साफ है, देर रात तक उनका वर्क या फिर किसी भी कारण जागना। ऐसे में अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो शरीर में एनर्जी नहीं रहती, लिहाजा आप फिर सो जाते हैं। लेकिन डायटीशियन और स्किन डॉक्टर श्रेया ने हाल इस समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला है जिसे फॉलो कर आप आसानी से सुबह उठने की आदत डाल सकते हैं। श्रेया के अनुसार, किशमिश का सेवन कर आप सुबह एनर्जी के साथ उठ सकते हैं।

सुबह के वक्त क्यों खानी चाहिए भीगी किशमिश

डायटीशियन- डॉक्टर श्रेया ने हाल ही में सुबह जल्दी उठने और भीगी हुई किशमिश खाने को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वे क्यों सुबह जागने के बाद किशमिश खाती हैं। डॉक्टर पोस्ट के कैप्शन में लिखती हैं, 'मैं यहां एक डीएम यानी Direct Message का जवाब दे रही हूं। किसी ने मुझसे पूछा कि मैंने अब भीगी हुई किशमिश खाना क्यों शुरू कर दिया है? क्या मैं एक रात का उल्लू और अरली वर्ड यानी सुबह की सैर करने वाली पक्षी बन रही हूं।' किशमिश ऊर्जा, सूक्ष्म पोषक तत्वों - विटामिन बी, सी, आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सिडेंट जैसे फेरुलिक एसिड, क्वेरसेटिन आदि से भरपूर होती है। इसके अतिरिक्त, इसमें आयरन, कैल्शियम और बोरॉन जैसे ट्रेस एंटीऑक्सिडेंट और खनिजों के साथ कुछ मात्रा में आहार फाइबर भी होते हैं। किशमिश मूल रूप से सूखे अंगूर हैं। इसलिए, वे अंगूर के अधिकांश पोषक तत्वों को बरकरार रखते हैं। आमतौर पर, साधारण चीनी के रूप में कार्बोहाइड्रेट, किशमिश का प्राइमरी कंपोनेंट होता है। किशमिश सुबह की भूख को दूर रखने में भी सहायक है! भिगोने के बाद फाइबर इसमें एक प्राकृतिक रेचक के रूप में कार्य करता है। यह हमें तब तक ऊर्जा प्रदान करता है, जब तक हमारा नाश्ता तैयार नहीं हो जाता। डायटीशियन कहती हैं कि जब आप अपने दिन की शुरुआत 5-6 भीगी हुई किशमिश खाने से करते हैं तो छोटी सी हैबिट आपके स्वस्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होती है। बकौल डॉक्टर, 'मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ स्टाइल में सुबह उठने के रूटीन को फॉलो कर रही हूं, इसलिए मुझे अपनी बॉडी को ट्रेंड करने, अपने पेट के लिए एक नई घड़ी सेट करने, अपने पाचन तंत्र को संदेश देने की जरूरत है कि 'अरे, इसकी आदत डाल लें। किशमिश के एक छोटे से आहार के जरिए मैं नए समय में ढलने की कोशिश में हूं। यह मूल रूप से मेरे सिस्टम के लिए एक एक्टिवेटर की तरह काम करती है, यह मेरे पाचन तंत्र को जगाती है और इसके माध्यम से मेरा पूरा शरीर थोड़ी सी ऊर्जा के साथ जाग जाता है।' डॉक्टर ने कुछ ऐसे सवालों के जवाब दिए जो आपके दिमाग में अक्सर रहते हैं। वह कहती हैं कि 'इन सभी वर्षों के लिए मेरी सर्केडियन राइम दिन के बाद के वक्त के अनुसार निर्धारित की गई थी। जैसे मैं देर से उठती हूं तो देर से खाती हूं इसलिए स्वाभाविक रूप से देर से पचाती हूं, देर से सोती हूं और फिर उठती भी देर से हूं। अगले दिन और परसों इसी समयनुसार रूटीन चलता रहा है। मेरा शरीर इन समयों से अच्छे से परिचित है और अब इसे काफी पसंद करती हूं, क्योंकि इस रूटीन में सालों से ढल चुकी हूं। अगर मैं अपने खाने की आदतों में बदलाव किए बिना अचानक जल्दी उठना शुरू कर दूं, तो शरीर इसे लड़ने की कोशिश तो करेगा, क्योंकि यह बिना किसी फ्यूल यानी आहार के थक जाएगा और अंत में, मैं जल्दी उठने की आदत को छोड़ सकती हूं।'

भीगी किशमिश खाने के फायदे

- ये एनर्जी का पावरहाउस है।
- भीगी हुई किशमिश ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है।
- इसे खाने से हमारा पाचन तंत्र हेल्दी रहता है।
- सुबह सुबह इसे खाने इम्यून सिस्टम भी बूस्ट रहता है।
- हड्डी के स्वास्थ्य के लिए भी भीगी हुई किशमिश बेहतर फूड है।
- एनीमिया को ठीक करने में मददगार है।
- किशमिश कमजोर लोगों के वजन बढ़ाने में भी मददगार है।
- सुबह फुर्ती के साथ जागना है तो खाएं किशमिश

सेहत और सौन्दर्य लाभ देता है ओट्स का नियमित सेवन

ओट्स यानी कि जौ या जई, एक प्रकार का खाद्य प्रदार्थ है, जिसे बहुत सारे अनाज को मिलाकर बनाया जाता है। ओट्स में कैल्शियम, फास्फोरस और पोटैशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये शरीर को कई प्रकार से फायदा करता है। आइए, जानते हैं ओट्स का नियमित सेवन कौन से सेहत और सौन्दर्य लाभ देता है -

- कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन-बी से भरपूर ओट्स आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।
- ओट्स में पाया जाने वाला इनोजिटॉल रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रित करता है, और उसे बढ़ने नहीं देता। यह शरीर में उपस्थित अतिरिक्त वसा को भी कम करता है।
- ओट्स पेट संबंधी रोगों में भी काफी लाभ देता है। यह कब्ज को दूर कर, पेट खराब होने की समस्या से निजात दिलाने में सहायक है।
- प्रतिदिन अपने नाश्ते या खाने में ओट्स को शामिल करने से डाइबिटीज की समस्या में लाभ होता है, क्योंकि यह इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित रखने में सहायक होता है।
- आपकी त्वचा को खूबसूरत बनाने के लिए भी ओट्स आपकी मदद कर सकता है। इससे बना फेस पैक चेहरे पर लगाने से त्वचा कोमल और स्वस्थ बनती है।
- ओट्स के चोकर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो जल्दी पेट भरने के साथ-साथ आपके शरीर में उर्जा संचार करता है, और यह वजन कम करने में बेहद लाभप्रद है।
- कैंसर से बचाव के लिए ओट्स का प्रयोग किया जा सकता है। इसके प्रयोग से हृदय रोग होने का खतरा भी कम होता है क्योंकि यह हृदय की धमनियों में वसा को जमने से रोकता है।
- शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण होने वाली समस्याओं जैसे चक्कर आना, दिल घबराना जैसी समस्याओं में ओट्स फायदेमंद है, क्योंकि इसकी प्रकृति ठंडी होती है।
- रूखी त्वचा या एक्जिमा जैसी तकलीफ में भी ओट्स सहायक होता है। ओटमील बाथ लेने से त्वचा की जलन समाप्त होती है और रूखापन भी खत्म हो जाता है।
- ओट्स को दूध में मिलाकर बनाए गए स्क्रब का प्रयोग करने से त्वचा की चमक बढ़ जाती है, और त्वचा लंबे संमय तक जवां और खूबसूरत दिखाई देती है।

डाइट में शामिल करें ये मसाले कई बीमारियों से बचेंगे

इस मौसम में आपको अपनी डाइट में कुछ चीजें जरूरी रूप से शामिल करनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे मसालों के बारे में जिन्हें इस मौसम में खाने पर आप कई कई बीमारियों से बच सकते है

काली मिर्च

काली मिर्च आपको सर्दी, खांसी, कफ, पाचन संबंधी समस्याओं से बचा सकती है साथ ही यह म्यूकस को शरीर से बाहर निकालने में भी काफी मददगार साबित होती है।

दालचीनी

दालचीनी का सेवन इस मौसम में गला खराब होने से तो बचाएगा ही, कफ को निकालने में भी मदद करेगा। यह प्राकतिक तौर पर शरीर में गर्माहट पैदा करने में सहायक है जिससे आप सर्दी जनित समस्याओं से बच जाते हैं।

हल्दी

हल्दी इन दिनों में गर्माहट का अच्छा स्त्रोत है और यह एंटी बैक्टीरियल व एंटी फंगल गुणों से भरपूर है। गर्म दूध में हल्दी का सेवन तो अमृत के समान माना गया है।

अदरक

अदरक वाली चाय का मजा ही कुछ और होता है। इन दिनों में इसके फायदे भी आपके लिए दुगुने होते हैं, क्योंकि यह न केवल शरीर को गर्माहट देती है बल्कि मौसम की बीमारियों से आपको बचाती है। सूखी अदरक यानि सौंठ का सेवन भी इस मौसम में लाभकारी है।

लहसुन

लहसुन को भून कर खाने से सर्दी ठीक होती है, यह तो दादी मां के नुस्खों में से एक है। ऐसे कई फायदों में लहसुन से मौसमी बीमारियों का बचाव भी शामिल है।

फुल टाइम जॉब करने वाली महिलाओं को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा

अगर आप एक महिला हैं। घर-ऑफिस की जिम्मेदारी बराबर से संभाल रही हैं, तो समय आ गया है कि आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। क्योंकि अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। कहीं ऐसा ना हो, कि भागदौड़ और काम के दबाव के चलते आप हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारी की गिरफ्त में आ जाएं। सुनकर थोड़ी हैरत होगी, लेकिन यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि एक स्टडी में सामने आई है।

यूरोपीय स्ट्रोक संगठन में पेश किए गए एक अध्ययन के अनुसार, महिलाओं में काम के दबाव और नींद की कमी के चलते हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। आमतौर पर डायबिटीज , आरटियल हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल , धूम्रपान और मोटापा ह्दय रोग के जोखिम में शामिल हैं। अध्ययन के अनुसार, वर्क प्रेशर, तनाव, नींद संबंधी विकार के कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले पुरूषों के मुकाबले महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे हैं। स्टडी के ऑथर कहते हैं कि परंपरागत रूप से पुरूषों को महिलाओं की तुलना में दिल के दौरे और स्ट्रोक से ज्यादा प्रभावित माना जाता है। लेकिन अब कुछ देशों में इस मामले में महिलाओं ने पुरूषों को पीछे छोड़ दिया है। अब काम का तनाव महिलाओं को दिल की बामारी की चेतावनी का संकेत दे रहा है।

तनाव और थकावट है कारण

अध्ययन में पाया गया कि भले ही पुरूषें में महिलाओं की तुलना में धूम्रपान करने और माटे होने की संभावना ज्यादा थी, लेकिन हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले सबसे ज्यादा महिलाओं में देखे गए। यूनिवर्सिटी हॉस्पीटल ज्यूरिख के न्यूरोलॉजिस्ट और उनकी टीम का कहना है कि महिलाओं में इन गंभीर बीमारियों में वृद्धि होने की वजह वर्कप्लेस पर ज्यादा काम का तनाव, नींद संबंधी विकार और थकावट है। चौकाने वाली बात ये है कि इन बीमारियों का जोखिम फुल टाइम जॉब करने वाली महिलाओं में सबसे ज्यादा देखा गया है। टीम के अनुसार, ऑफिस में फुल टाइम जॉब करने वाली महिलाओं पर घर और ऑफिस की जिम्मेदारी निभाने का दबाव उन महिलाओं के मुकाबले ज्यादा रहता है, जो तीन से चार घंटे की नौकरी करती हैं।

थकान और नींद संबंधी विकारों में हुई वृद्धि

रिसर्चर्स ने 2012, 2017 और 2020 के स्विस हेल्थ सर्वे में 22000 महिलाओं और पुरूषों के डाटा की तुलना की। इसमें उन्होंने पाया कि कार्डियोवस्कुलर डिसीज के लिए गैर पारंपरिक जोखिम वाले कारकों की रिपोर्ट करने वाली महिलाओं की संख्या में खतरनाक रूप से वृद्धि हुई। कुल मिलाकर काम के दौरान स्ट्रेस लेने वाले पुरूष और महिलाओं की संख्या 2017 में 59 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 66 प्रतिशत हो गई। जबकि काम के बाद थकान महसूस करने वालों की संख्या 23 प्रतिशत से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई। इस अवधि में नींद संबंधी विकारों की संख्या 24 प्रतिशत से बढ़कर 29 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई। नींद संबंधी विकार के मामले जहां पुरूषों में 5 प्रतिशत बढ़े, वहीं महिलाओं में 8 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है।

इस रिसर्च के बाद यह तो साफ है कि अब हार्ट अटैक और स्ट्रोक पुरूषों से जुड़ी बीमारी नहीं रही, बल्कि अगर ध्यान न दिया जाए, तो काम के दबाव के चलते महिलाओं में भी इन गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे हालातों से बचने के लिए महिलाओं को काम करते हुए कम तनाव और अच्छी नींद लेने की बहुत जरूरत है।

14 वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ

खिलाड़ियों में दिखेगा अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रीय एकता का जज्बा : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

दुर्ग। प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई में 23 से 27 फरवरी तक आयोजित 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ आज उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय पुलिस कंट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 437 प्रतिभागियों जिसमें 285 पुरुष एवं 152 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। टीमों के साथ मैनेजर एवं कोच भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी टीम मैनेजरों से परिचय प्राप्त किया। तीरंदाजी प्रतियोगिता के तीन प्रमुख इवेंट इंडियन राउंड, रिकर्व एवं कंपाउंड शामिल हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्रीय बलों से आए सभी खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है कि इतने प्रतिष्ठित स्तर की अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर राज्य को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने का सशक्त साधन हैं। देश के कोने-कोने से आए खिलाड़ी यहां एक मंच पर एकत्र हुए हैं, जो भारत की विविधता में एकता की भावना को साकार करते हैं। विशेष रूप से पुलिस एवं केंद्रीय बलों के खिलाड़ी, जो देश की सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं, खेल मैदान में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे है। प्रतियोगिता में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों की उपस्थिति इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ाती है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड से सम्मानित किया जाना पूरे प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, ड्रोन के माध्यम से पेट्रोलिंग और सुरक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार ये सभी छत्तीसगढ़ पुलिस की दक्षता और प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार, प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निगम द्वारा उनके आवास, स्वास्थ्य, परिवहन और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और पूर्व में वेटलिफ्टिंग सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन इसका उदाहरण है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन कर, अपने-अपने राज्यों और बलों का नाम रोशन करें। दुर्ग महापौर मती अलका बाघमार ने कहा कि खेल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। खेल शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेशों से आए खिलाड़ियों के बीच सामंजस्य और एकता की भावना खेलों से ही विकसित होती है। सभी खिलाड़ियों के लिए निवास, परिवहन एवं सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि उन्हें सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण मिल सके। इस अवसर पर डीजीपी अरूण देव गौतम, एडीजी विवेकानन्द सिन्हा।

अवैध काष्ठ परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, चार वाहन जब्त

दुर्ग। वनमंडलाधिकारी दुर्ग वनमंडल द्वारा 23 एवं 24 फरवरी 2026 को अवैध काष्ठ परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्यवाही की गई। इस दौरान अवैध लकड़ी परिवहन में संलिप्त चार वाहनों को जब्त किया गया। प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर वनमंडलाधिकारी दुर्ग के निर्देशन एवं उप वनमंडलाधिकारी के नेतृत्व में उड़नदस्ता दल दुर्ग वृत्त तथा परिक्षेत्र सहायक भिलाई-03 की संयुक्त टीम ने 23 एवं 24 फरवरी को प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक विशेष रात्रि गश्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अवैध रूप से काष्ठ परिवहन करते हुए कुल चार वाहन पकड़े गए। वाहन क्रमांक सीजी-10सी 3389 में कहुआ मिश्रित जलाऊ लकड़ी, टाटा 1109, क्रमांक सीजी-08 एल 3736 में कहुआ मिश्रित जलाऊ लकड़ी, टाटा 1109, क्रमांक सीजी-04 जेसी 9290 में कहुआ मिश्रित गोला, टाटा 1109 क्रमांक सीजी-04 एमएफ6945 में कहुआ मिश्रित जलाऊ लकड़ी, सभी वाहन अवैध काष्ठ से लदे पाए गए, जिन्हें विधिवत जब्त कर पुलगांव एवं पाटन डिपो में जमा कराया गया। उक्त प्रकरणों में संबंधित आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 79/11 23.02.2026 तथा 91/3, 91/4, 91/5 दिनांक 24.02.2026 के तहत मामला दर्ज कर विधि अनुसार वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

पाटन ब्लॉक के धान खरीदी केंद्रों में शेड निर्माण, बाउंड्री वॉल के लिए करोड़ों रुपए का भूमि पूजन संपन्न

दुर्ग सांसद विजय बघेल हुए शामिल

पाटन। पाटन ब्लॉक अंतर्गत आने वाले सेवा सहकारी समिति सावनी और केसरा में दुर्ग सांसद विजय बघेल के कर कमलों से मंडी बोर्ड मद से लगभग 05 करोड़ का धान खरीदी केंद्रों में शेड निर्माण, बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन किया गया। सावनी, सांकरा, झीट,जामगांव एम, बटंग, जमराव, घुघवा, केसरा,सोरम, डंगनिया, तेली गुंडरा, बठेना, जामगांव एम, भरर, फेकारी सहित अन्य सेवा सहकारी समितियों में प्रत्येक सोसायटी में 19 लाख 13 हजार रुपए का शेड निर्माण बाउंड्री वॉल हेतु भूमि पूजन सावनी सेवा सहकारी समिति और केसरा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल रहे। अध्यक्षता सुरेंद्र कौशिक जिलाध्यक्ष भाजपा दुर्ग ने किया। विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सभापति नीलम राजेश चंद्राकर, जिला पंचायत सभापति कल्पना नारद साहू, जनपद उपाध्यक्ष कमलेश वर्मा, भाजपा नेता संजय दानी,सांसद प्रतिनिधि राजा पाठक, जनपद सांसद प्रतिनिधि राजेश चंद्राकर, मंडल अध्यक्ष कमलेश चंद्राकर, कमलेश साहू, ज्योति प्रकाश साहू, रानी बंछोर, अम्लेश्वर पालिका अध्यक्ष दयानंद सोनकर, नगर पंचायत पाटन अध्यक्ष योगेश निक्की भाले, जनपद रेखा अरविंद जोशी, जनपद सदस्य संतोषी ठाकुर, जनपद सदस्य भावना निषाद, भाजपा नेता लालेश्वर साहू,लोकमनी चंद्राकर रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी,होली के पहले अंतर राशि किसानों को मिलने वाली है। धान खरीदी केंद्रों में करोड़ों का विकास कार्य की आधार शिला रखा गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के वार्षिक बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रखा है जो विकसित भारत की ओर अग्रसर है ।सबका साथ सबका विकास करने वाली बजट छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर मंडल महामंत्री निर्मल जैन, कैलाश यादव, डॉ सुरेश साहू, धर्मेंद्र कौशिक,सरपंच सावनी रामेश्वरी जांगड़े ,सरपंच झीट रूपेंद्र राजू साहू ,सरपंच सांकरा रवि सिंगौर, सरपंच मोतीपुर मोहन सिंगौर, सरपंच खुड़मुड़ी गुलाब जोशी, तरीघाट सरपंच चंद्रिका साहू,पूर्व सरपंच धर्मेंद्र सोनकर रमाकांत यादव, बेनी साहू,मनबोध, साहू, धर्मेंद्र कौशिक, अध्यक्ष रमाकांत यदु,सुनील वर्मा,तुकेश्वर निर्मलकर,दानी वर्मा, पारखत साहू, अंगेश सिन्हा, प्रेमलाल साहू,राजेश बंछोर, बलदाऊ वर्मा, प्रणव चंद्राकर, युराज साहू,अनिता वर्मा, बिरेंद्र ठाकुर,मोहित अमृत,गैंडलाल गजेंद्र,गजेंद्र वर्मा,दानेश्वर साहू, सुरेंद वर्मा,अजित ठाकुर, फेरहा राम धिवर शिवा साहू, मनीष कोसले,रोहित वर्मा, गोविंद वर्मा।

जहां जाम से लोग होते थे परेशान, वहीं अब हरियाली का सुकून, आज वहां चमक रहा है सुंदर गार्डन

अतिक्रमण हटते ही बदली इंदिरा मार्केट, पुराना बस स्टैंड तस्वीर, सड़क किनारे खिला सुंदर गार्डन, ठेले-खोमचे से मुक्त हुआ इलाका, अब एलईडी रोशनी से जगमगाता स्थल

दुर्ग। शहर के हृदय स्थल पुराने बस स्टैंड के सामने सड़क किनारे की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। कुछ माह पहले तक यह स्थान अतिक्रमण और अव्यवस्था का केंद्र बना हुआ था। ठेले-खोमचे और अस्थायी कब्जों के कारण यहां रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती थी, जिससे खरीदारी के लिए आने वाले नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। महापौर अलका बाघमार एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल सख्त निर्देश पर नगर निगम के बाजार विभाग और अतिक्रमण विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे से कब्जे हटवाए गए और जगह को पूरी तरह खाली कराया गया। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि 'मोर शहर मोर जिम्मेदारी' सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि शहर को संवारने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत व सख्ती के साथ चलाए गए अभियान के तहत अतिक्रमण हटाया गया। महापौर ने कहा कि जहां कभी अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती थी, आज वही स्थान सुंदर गार्डन, आकर्षक लाइटिंग और स्वच्छ वातावरण के साथ शहर की नई पहचान बन चुका है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि शहर की सुंदरता और व्यवस्था बनाए रखने में सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अतिक्रमण से आकर्षण तकः इंदिरा मार्केट कपड़ा लाइन का बदला स्वरूप बड़ी मुश्किलों के बावजूद नगर निगम प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाकर इतिहास रचा, महापौर अलका बाघमार की सोच साकार, इंदिरा मार्केट में सौंदर्यकरण का दिखाने लगा है असर

'मोर शहर मोर जिम्मेदारी' के तहत बना आकर्षक गार्डन–खाली कराई गई भूमि को यूं ही नहीं छोड़ा गया। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत मेगा ग्रुप एजेंसी के संचालक मनीष परख ने 'मोर शहर मोर जिम्मेदारी' अभियान से प्रेरित होकर यहां एक सुंदर गार्डन विकसित कराया।गार्डन में हरियाली के साथ-साथ आम नागरिकों के बैठने के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है, जिससे यह स्थान अब विश्राम स्थल के रूप में भी विकसित हो रहा है।

एलईडी लाइटिंग से निखरी सौंदर्य की नई पहचान–स्थल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आकर्षक एलईडी लाइटिंग लगाई गई है। शाम ढलते ही यह क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठता है और राहगीरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। रात के समय यह स्थान अब सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित नजर आता है, जो शहर की बदलती तस्वीर को दर्शाता है।

जल्द पूरा होगा शेष सौंदर्यीकरण कार्य–संचालक मनीष पारख ने बताया कि लाइटिंग एवं कुछ सौंदर्यीकरण कार्य अभी शेष हैं, जिन्हें शीघ्र ही पूर्ण कर आम जनता को समर्पित किया जाएगा। जहां कभी अव्यवस्था और जाम की स्थिति रहती थी, वहीं अब हरियाली, रोशनी और स्वच्छता का संदेश देता यह स्थल शहर के सकारात्मक परिवर्तन का उदाहरण बन चुका है।

नो हेलमेट, नो पेट्रोल आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बैठक संपन्न

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंग की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा उपायों के अंतर्गत नो हेलमेट, नो पेट्रोल आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पेट्रोल पम्प एसोसिएशन के सदस्यों एवं संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग से एएसपी सुखनंदन राठौर एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर सिंग ने दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल न दिए जाने के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कदम जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। उन्होंने पेट्रोल पम्प संचालकों को आमजन के बीच इस संबंध में व्यापक जनजागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए। साथ ही, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने की बात कही गई। एएसपी सुखनंदन राठौर ने भी बैठक में हेलमेट की अनिवार्यता पर जोर देते हुए सभी पेट्रोल पम्प संचालकों से प्रशासन के आदेशों का पालन करने का आग्रह किया।

बैठक के दौरान पेट्रोल पम्प संचालकों ने भी अपनी-अपनी समस्याओं एवं व्यावहारिक कठिनाइयों से प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त, सभी पेट्रोल पम्पों पर आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हवा, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

स्वच्छ दुर्ग की ओर बड़ा कदमः खटालों से गोबर प्रबंधन पर निगम का सख्त निर्णय

- नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना तयः स्वच्छता में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

दुर्ग। महापौर अलका बाघमार की सख्तीः शहर को स्वच्छ व सुव्यवस्थित बनाने की पहल,नगर पालिक निगम दुर्ग की महापौर अलका बाघमार द्वारा शहर को सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित रखने के उद्देश्य से आज स्वास्थ्य विभाग प्रभारी निलेश अग्रवाल,पार्षद गुलाब वर्मा स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता की मौजूदगी में शहर के समस्त खटाल संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक ली गई। बैठक में शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा खटाल क्षेत्रों में व्याप्त गंदगी की समस्या पर गंभीर चर्चा की गई।

खटाल क्षेत्रों में गंदगी पर जताई नाराजगी–बैठक में यह बात सामने आई कि कई खटाल संचालकों द्वारा गोबर को सड़कों एवं सार्वजनिक खाली स्थानों पर रखा जाता है तथा नालियों में बहा दिया जाता है, जिससे खटाल क्षेत्रों सहित आसपास के स्थानों में बदबू एवं गंदगी फैल जाती है। इस संबंध में शहर के नागरिकों ने महापौर के समक्ष अपनी समस्याएं रखी थीं, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए यह बैठक आयोजित की गई।

प्रतिदिन गोबर संग्रहण के लिए निगम करेगा बेंडर नियुक्त–निगम द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रतिदिन एक अधिकृत बेंडर नियुक्त किया जाएगा, जो प्रत्येक खटाल से गोबर का नियमित संग्रहण करेगा। सभी खटाल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने खटाल में गोबर एकत्रित कर संबंधित बेंडर को उपलब्ध कराएं, ताकि शहर में गंदगी की स्थिति उत्पन्न न हो।

नियम उल्लंघन पर होगी जुर्माने की कार्रवाई–महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि निर्धारित व्यवस्था के बाद भी सड़कों या नालियों में गोबर पाया जाता है, तो संबंधित खटाल संचालक के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था के लिए खटाल संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

1 मार्च 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था–उक्त प्रक्रिया का क्रियान्वयन 1 मार्च 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। महापौर अलका बाघमार ने सभी संचालकों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि स्वच्छ एवं सुंदर दुर्ग शहर के निर्माण में सभी की सहभागिता आवश्यक है।

राजगामी में खेल, संपदा से बाबूओं की चांदी, लीज की दुकानों पर अवैध निर्माण, कईयों ने किराए पर चढ़ा दी

- नियमों का ताक में रख कई व्यापारियों और दुकानदारों ने की मनमानी

राजनांदगांव। राजगामी संपदा न्यास की प्रॉपर्टी पर मनमानियां चल रही है। बड़ी बात इस विभाग को पूरा खेल बाबूओं के हाथ में हैं और जमकर चांदी काट रहे हैं। राजगामी की जमीन पर जो निर्माण हुए हैं, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन संस्कारधानी में खुलेआम ये काम किया गया

कईयों ने दुकानें किराए पर चढ़ा रखी है। इसकी पूरी जानकारी विभागीय बाबूओं को हैं। लेकिन वे कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं और राजगामी न्यास को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गोलबाजार और हाइवे कई ऐसी दुकानें हैं, जिसे राजगामी संपदा की ओर से लीज पर दिया गया हे। लेकिन इनसे जो शुल्क लिया जाता है वह काफी कम है। लंबे समय से व्यापारी और दुकानदार यहां डटे हैं। इस कारण उन्होंने राजगामी की प्रॉपर्टी पर हक जमा लिया है और उसके मूल रूवरूप से भी छेड़छाड़ कर परिवर्तन कर दिया है। जबकि यह नियमों के खिलाफ है। यह छिपाया नहीं जा सकता, दूसरी तरफ राजगामी संपदा के कर्मचारियों का निरीक्षण होता रहता है। इसके बाद भी आंख मूंदकर बैठे हुए हैं।

मिलीभगत से नकारा नहीं जा सकता–इस पूरे मामले में विभागीय कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच मिलीभगत को नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि राजगामी की प्रॉपर्टी पर किस आधार पर निर्माण किया गया, वह भी बिना अनुमति के। उस पर सीधी कार्रवाई होनी थी। लेकिन ऐसा अब तक नहीं किया गया। दूसरी तरफ कई दुकानदार को अतिरिक्म कब्जा कर अवैध निर्माण करके बैठे हैं और उसे किराए पर दे चुके हैं। इससे वे मोटा किराया भी वसूल रहे हैं। लेकिन राजगामी संपदा के जिम्मेदार इससे दूरी बनाए हुए हैं इस कारण उनकी सांठगांठ स्पष्ट नजर आ रही हे।

शिकायत हुई तो उस पर कार्रवाई नहीं–कई ऐसा समय आया जब राजगामी की संपत्ति पर कब्जा और अवैध निर्माण को लेकर शिकायत की गई। लेकिन उसे भी बाबू अपने स्तर पर ही निपटा देते हैं। मतलब ऐसे मामलों में कार्रवाई होने ही नहीं दी जाती। क्योंकि इसमें राजगामी के कर्मचारियों की रूचि है।

बीआईटी दुर्ग में ई-ऑफिस क्रियान्वयन के लिए दो पालियों में प्रशिक्षण आयोजित

दुर्ग। शासकीय कार्यों को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए बीआईटी दुर्ग में ई-ऑफिस क्रियान्वयन हेतु दो पालियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में सामान्य प्रशासन विभाग से आए मास्टर ट्रेनरों ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न ऑनलाइन प्रणालियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण की प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। वहीं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई, जिसमें सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनरों द्वारा ई-ऑफिस, स्पायरो एवं ई-एचआरएमएस से संबंधित कार्यप्रणाली की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारी एवं कर्मचारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया तथा ऑनलाइन फाइल प्रबंधन, ऑनलाइन सम्पत्ति प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन एवं अन्य कार्यालयीन प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान डेमो के माध्यम से फाइल संचालन, नोटशीट तैयार करने तथा ऑनलाइन अनुमोदन की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण देने का प्रयोजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों को पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए सक्षम बनाना है। इससे कार्यों में पारदर्शिता आएगी, समय की बचत होगी तथा कार्यालयीन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित की जा सकेगी। इस दौरान वनमंडलाधिकारी दीपेश कपिल, जिला पंचायत के सीईओ बी.के. दुबे, अपर कलेक्टर मती योगिता देवांगन, अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर हितेश पिस्दा एवं उत्तम ध्रुव सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

वैवाहिक कार्यक्रम के बाद फैली गन्दगी, निगम ने थमाई नोटिस

सफाई व्यवस्था पर दिया जा रहा जोर, सख्ती भी

राजनांदगांव। साफ -सफाई का जायजा लेने निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा सुबह वार्ड विजिट कर रहे है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रोज सफाई देख साफ सफाई में जोर देने सफाई कर्मचारियों को निर्देशित करने के साथ साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं मलमा मण्डप के तहत कार्यवाही करने तथा नागरिको को स्वच्छता से जोडने स्वास्थ्य अमला को निर्देश दे रहे है। उनके द्वारा शहर के प्रमुख मार्ग सहदेव नगर रोड, मानव मंदिर चौक, पोस्ट आफिस चौक, रेल्वे स्टेशन रोड में साफ -सफाई का जायजा लेकर बाबा फतेहसिंह हाल में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान रोड में पाली पापर बिखरा देख संबंधित को नोटिस जारी कर कार्यवाही करने कहा। आयुक्त विश्वकर्मा आज सुबह आर.के.नगर व सहदेव नगर रोड में साफ -सफाई का जायजा लेकर सफाई कर्मियों से चर्चा कर नाली अंदर तक साफ कर कचरा निकालने तथा प्रभारी से उठवाने के लिये कहा। मानव मंदिर चौक में दुकाने खुलने से पहले सफाई करने, आवागमन बाधित स्थल से फल दुकान हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्ड प्रभारी से कहा कि सफाई के अलावा अतिक्रमण करने या मटेरियल रखने वालों को समझाईस देवे अपालन पर कार्यवाही करे। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखकर नागरिको को अपने घर के आस पास साफ सफाई रखने, फिटबैक लेने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने आर.के.नगर रोड की स्ट्रीट लाईट बंद करने का समय परिवर्तन कर 6 बजे बंद कराने विद्युत प्रभारी को निर्देशित किए। इसी प्रकार सहदेव नगर रोड में बाबा फतेहसिंह हाल के पास पाली पापर बिखरे देख संबंधित को नोटिस जारी कर कार्यवाही करने कहा। उन्होंने कहा कि फतेहसिह हाल के अलावा अन्य मांगलिक भवनों के संचालको को साफ -सफाई रखने, बरात के दौरान सडक में पाली पापर व कचरा नही बिखराने समझाईस देवे अपालन पर कार्यवाही करे.

आई.टी.आई. पुलगांव में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, 40 विद्यार्थियों को निःशुल्क हेलमेट वितरण

दुर्ग। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासकीय आई.टी.आई. पुलगांव में सड़क सुरक्षा जागरूकता कायक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन हेतु प्रेरित किया गया तथा लगभग 40 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को हेलमेट पहनने, कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने एवं वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रखने की अपील किया जा रहा है, जिससे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। Email : loktantraprahrinews@gmail.com